वर्ष-10, अंक-4, जनवरी-2025

मूल्यः ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611

राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

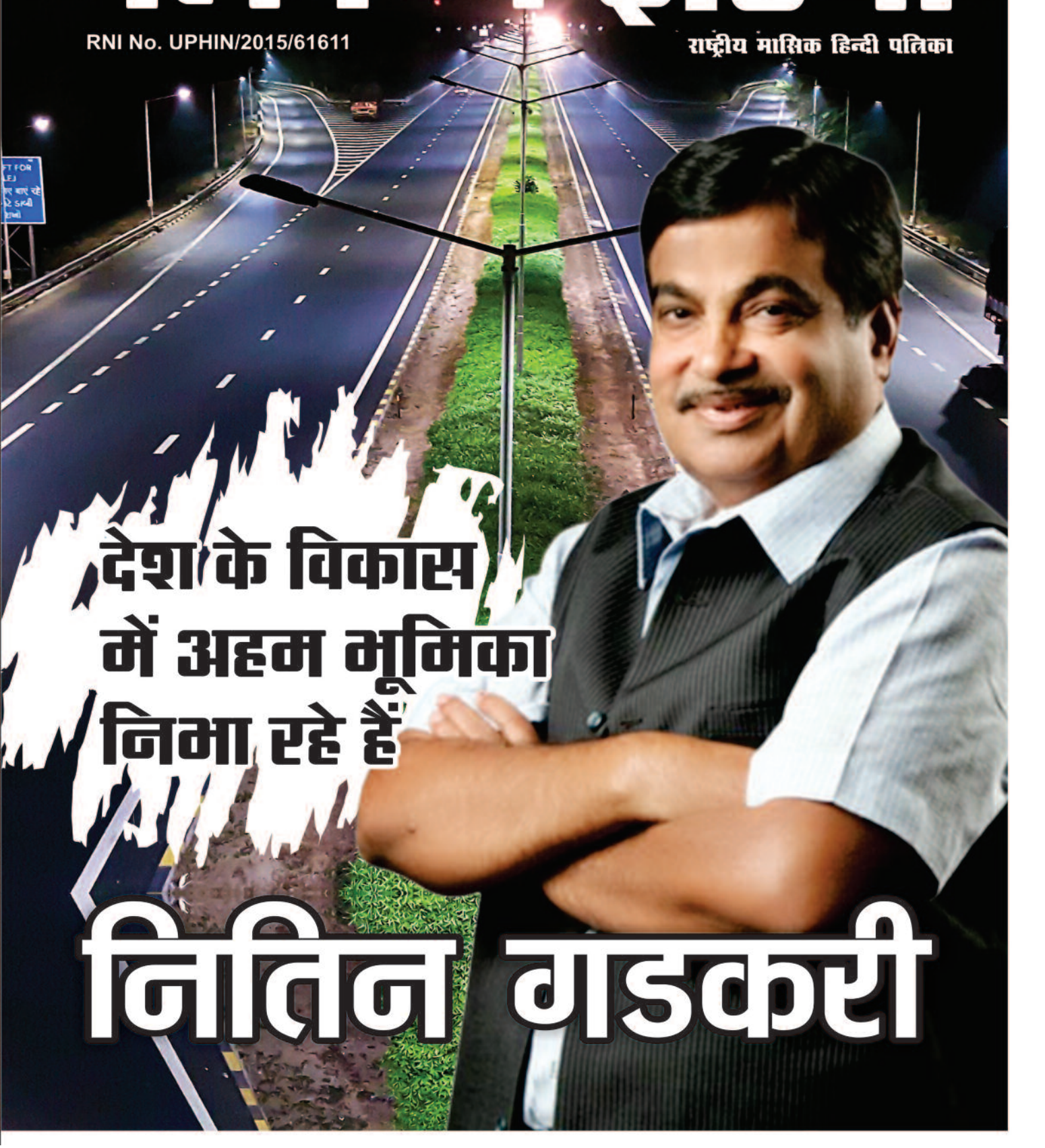

देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं

नितिन गडकरी

देश में
नंबर वन
उत्तर प्रदेश

एक्सप्रेसवे प्रदेश
उत्तर प्रदेश

सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य
6 क्रियाशील, 7 निर्माणाधीन

- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे : लखनऊ से गाजीपुर (341 किमी.)
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे : चित्रकूट से इटावा (296 किमी.)
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे : आगरा से लखनऊ (302 किमी.)
- यमुना एक्सप्रेसवे : ग्रेटर नोएडा से आगरा (165 किमी.)
- दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे : मेरठ से दिल्ली (82 किमी.)
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (25 किमी.)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

अन्दर के पेजों में...

वर्ष- 10 अंक- 4

जनवरी - 2025

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या है संबंध जानें इससे जुड़ी पौराणिक कथा — पेज 03

प्रशासनिक अनुभव की समृद्ध पृष्ठभूमि से गाजियाबाद को नई दिशा देंगे नये डीएम दीपक मीणा — पेज 10

इंजीनियर से आईएएस बने अतुल वत्स की कार्यशैली... — पेज 11

डीसीपी राजेश कुमार की कार्यशैली अपराधियों में खौफ — पेज 14

बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आईएएस अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक — पेज 15

आईपीएल: कौन-कितना मजबूत — पेज 54

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

बिना हादसे के कुंभ का आयोजन करना बड़ी चुनौती

ललित कुमार
सम्पादक

प्रयागराज कुंभ मेले में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आयोजन बिना किसी हादसे के संपन्न हो। मगर रविवार को मेले के एक हिस्से में लगी आग से यही स्पष्ट हुआ कि व्यवस्था के हर मोर्चे पर चाक-चौबंद होने के तमाम दावों के बरक्स कुछ लोगों ने लापरवाही बरती। नतीजतन, मेला क्षेत्र के गीता प्रेस शिविर में रसोई गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई। गनीमत बस यह रही कि इसके बाद आग बुझाने और बचाव में काफी तत्परता देखी गई, जिसकी वजह से आग के दायरे को समेटने और उस पर काबू पाने में कामयाबी मिली और कम से कम किसी की जान नहीं गई। वरना, जिस स्तर पर आग लगी और उसकी लपटें उठीं, उसमें घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बचाव दल की ओर से इस स्तर की त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तो जानमाल के नुकसान का दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता था।

किसी भी धार्मिक आयोजन में होने वाले जमावड़े में लापरवाही की वजह से आग लगने या भीड़ के बेकाबू होने के बाद हादसा न होने देना ही सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। प्रयागराज में कुंभ की शुरूआत के समय ही जितने बड़े पैमाने पर लोगों के जुटने का अनुमान लगाया गया था, उसमें सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी समूचे मेला क्षेत्र में व्यवस्था के स्तर पर सौ फीसद सुरक्षा की थी। किसी एक जगह बरती गई मामूली लापरवाही भी गंभीर जोखिम पैदा कर सकती थी।

व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिस तरह के व्यापक इंतजाम किए गए, अलग-अलग महकमों से भारी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया गया, उससे दुर्घटनाओं को रोकने और उन पर काबू पाने की कोशिश जरूर दिखी। मगर असली चुनौती किसी भी हादसे की संभावना तक को शून्य करना था। इसमें फिलहाल एक मोर्चे पर नाकामी सामने आई है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सबक लेकर सभी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और बचाव के ऐसे इंतजामों में कोई भी कोताही नहीं की जाएगी, ताकि कुंभ कम से कम बचे हुए वक्त में अच्छी स्मृतियों के साथ संपन्न हो।

मेला क्षेत्र के गीता प्रेस शिविर में रसोई गैस सिलेंडर के फटने से आग लग गई। गनीमत बस यह रही कि इसके बाद आग बुझाने और बचाव में काफी तत्परता देखी गई, जिसकी वजह से आग के दायरे को समेटने और उस पर काबू पाने में कामयाबी मिली और कम से कम किसी की जान नहीं गई। वरना, जिस स्तर पर आग लगी और उसकी लपटें उठीं, उसमें घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बचाव दल की ओर से इस स्तर की त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तो जानमाल के नुकसान का दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता था।

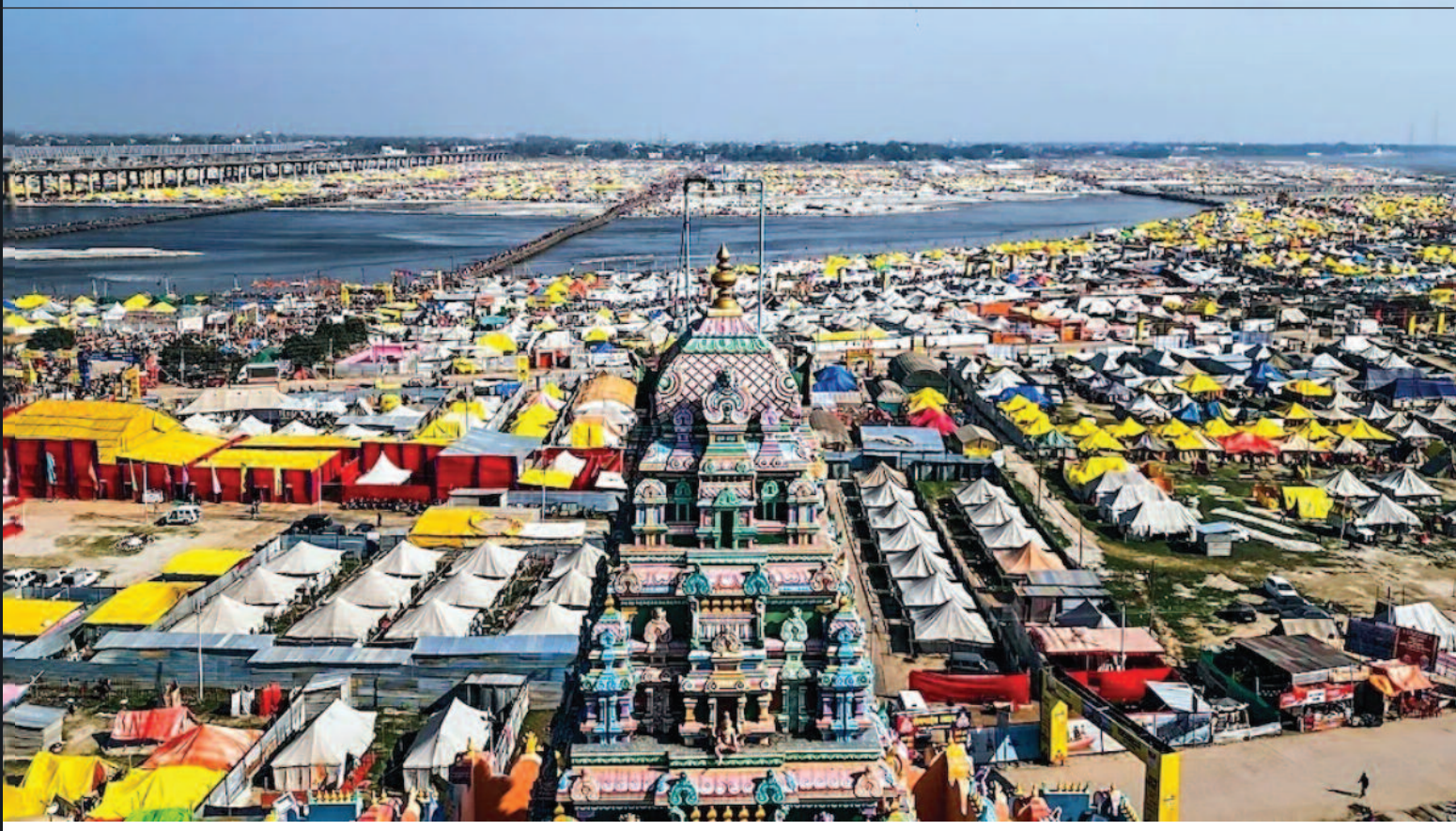

महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या है संबंध जानें इससे जुड़ी पौराणिक कथा

चरण सिंह

हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेले का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यह पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और सनातन संस्कृति की महानता को दशार्ता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कुंभ निकला था, उस अमृत कुंभ से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं। जिन स्थानों पर यह अमृत की बूंदे गिरी थी, उन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। उन स्थानों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक प्रमुख स्थान हैं, जहां कुंभ का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2025 में यह महापर्व प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा।

करोड़ों रुद्राक्ष और 11 हजार त्रिशूल से द्वादश ज्योतिर्लिंग का होगा श्रृंगार

वर्ष 2025 का महाकुंभ भव्यता और आस्था का संगम होगा, 5.51 करोड़ रुद्राक्ष और 11,000 त्रिशूल से द्वादश ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार होगा। मौनी बाबा शिविर में विशेष यज्ञ और सवा करोड़ दीपक जलाए जलाएंगे, सुरक्षा के लिए कोरस कमांडो तैनात की तैनाती की गई हैं।

महाकुंभ में नहीं खोएगा अब एक भी बच्चा

महाकुंभ 2025 की तैयारियों के बीच बच्चों के खोने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशनों पर बाल अधिकार डेस्क बनाने का निर्णय लिया है, यहां विशेष अधिकारी बच्चों की मदद करेंगे, जो माता-पिता से बिछड़े या रास्ते में भटके बच्चों को तुरंत सहायता प्रदान करेंगे, इसके अलावा चाइल्ड हेल्प लाइन 24 घंटे काम करेगी, जिससे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ यात्रा सरल और सुरक्षित बनी रहे।

महाकुंभ 2025 में 82 देशों के मीडिया का होगा कवरेज

महाकुंभ 2025 तीर्थराज प्रयागराज में एक अद्वितीय आध्यात्मिक उत्सव होगा, जहां सनातन धर्म की पवित्र परंपराओं के साथ डिजिटल तकनीकी प्रगति का संगम देखने को मिलेगा। इस आयोजन को कवर करने के लिए 82 देशों के मीडिया समूह उत्सुक हैं, जिनका आगमन 11-12 जनवरी तक होगा। एडीएम मेला ने मीडिया शिविर और सेंटर की तैयारी की जानकारी दी है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जो हर तीन साल में चार प्रमुख स्थानों पर होता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन अर्धकुंभ हर छह साल में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, और पूर्णकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है जिसका स्थान ज्योतिषीय गणना के आधार पर तय किया जाता है।

कुंभ में अलग-अलग अखाड़े

कुंभ मेला 2025 की शुरूआत 13 जनवरी से हो रही है, कुंभ में अलग-अलग अखाड़े होते हैं और हर अखाड़े में तरह-तरह के साधु संत आते हैं। जिनको देखने के लिए श्रद्धालु उनके अखाड़े में पहुंचते हैं, वहां आ रहे अजब-गजब साधुओं में एक हाथ वाले बाबा भी शामिल होते हैं, इनका नाम महंत महाकाल गिरी होता है, जो लंबे समय से हठ योग करते आ रहे हैं, इन्होंने अपना एक हाथ त्याग दिया है और उसे हमेशा ही ऊपर खड़ा रखते है। तपस्या के लिए इन्होंने अपना एक हाथ निर्जीव कर दिया है।

पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पहले जरूर करें ये तीन काम

पहला नियम

यदि आप भी महाकुंभ में डुबकी लगाने जाने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि गृहस्थ्य लोग 5 डुबकी लगाएं. पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब गृहस्थ्य लोग महाकुंभ में 5 बार डुबकी लगाते हैं तो कुंभ स्नान पूरा माना जाता है।

दूसरा नियम

महाकुंभ के दौरान कभी भी नागा साधुओं से पहले डुबकी ना लगाएं, क्योंकि महाकुंभ के दौरान सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं और डुबकी लगाते हैं, फिर अन्य लोग डुबकी लगाते हैं। इसलिए अगर आप भी पवित्र नदी में नागा साधुओं के स्नान के बाद ही स्नान करें वरना ये नियमों का उल्लंघन व धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जायेगा व शुभ फलों की प्राप्ति भी नहीं होगी।

तीसरा नियम

महाकुंभ में पवित्र नदी में स्नान के बाद अपने दोनों हाथों से सूर्यदेव को अर्ध्य जरुर दें, यह अर्ध्य आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत भी करता है साथ ही ऐसा करने से आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी।

इन नियमों का पालन करने से आप महाकुंभ में स्नान करते हैं, तो आपको कई तरह के लाभ मिलते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. हालांकि इससे आपको आध्यात्मिक रुप से भी विकास करने में मदद मिलेगी।

'एंबेसडर कार' वाले बाबा की क्यों है चर्चा ? 'टार्जन बाबा' के नाम से भी लोकप्रिय

महाकुंभ के लिए बाबाओं का प्रयागराज पहुंचना जारी है। इसी क्रम में प्रयागराज में एंबेसडर बाबा भी पहुंचे हैं। एंबेसडर कार वाले बाबा को टार्जन बाबा कहकर भी लोग बुलाते हैं। बाबा का असली नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है और वह मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। वह अपने साथ एक एंबेसडर कार लेकर चलते हैं और उसी में रहते भी हैं। उनकी कार काफी चर्चा का केंद्र बनी हुई है।

महाकुंभ में कैसे होती है करोड़ों लोगों की गिनती

पहले से कितनी अलग है क्राउड असेसमेंट की ये तकनीक

महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. ऐसे में सटीक अनुमान के लिए मेला क्षेत्र में अक्बेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही निश्चित दायरे में भीड़ के घनत्व को भी मापा जाता है।

संजीव कुमार

प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र संगम में स्नान करने का अनुमान है. बीते दो दिनों की ही बात करें तो पहले दो दिन में ही 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कुंभ मेले में आ चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. लेकिन कुंभ में आने वाली इतनी भारी भीड़ की गिनती आखिर कैसे होती है. साथ ही यह सिर्फ अनुमान है या फिर इसके पीछे किसी सटीक मैथड का भी इस्तेमाल किया जाता है. तो आज आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहे जाने वाले कुंभ में लोगों की गिनती करने के लिए क्या-क्या तकनीक अपनाई जाती रही हैं.

कैसे हो रही भीड़ की गिनती

महाकुंभ 2025 की बात करें तो इस बार का कुंभ बेहद खास है क्योंकि हर 12 साल बाद लगने वाले इस कुंभ में 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि अब तक 12 कुंभ पूरे हो चुके हैं. इसी वजह से इसे महाकुंभ कहा जा रहा है और इसमें आने वाला श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा है. ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार अकबेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है.

सरकार ने महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और इस टीम का नाम है क्राउड असेसमेंट टीम. यह टीम रियल टाइम बेसिस पर

महाकुंभ में आने वाले लोगों की गिनती कर रही है और इसके लिए ऐसे खास कैमरों की मदद ली जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों की गिनती कर रहे हैं. लोगों को स्कैन कर रहे हैं, यह कैमरे महाकुंभ में आने वाले लोगों के चेहरों को स्कैन करते हैं और वहां मौजूद भीड़ के हिसाब से यह अनुमान लगाते हैं कि कितने घंटे में कितने लाख लोग महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आए हैं. इस समय महाकुंभ के पूरे मेला क्षेत्र में ऐसे 1800 कैमरे लगे हुए हैं. इसके अलावा यही टीम लोगों की गिनती करने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है जिनसे एक निश्चित क्षेत्र में भीड़ के घनत्व को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि एक दिन में कितने लोग महाकुंभ के आयोजन में शामिल हो रहे हैं. कितने लोगों ने संगम में स्नान किया है.

ड्रोन और अक्तकनीक की मदद

महाकुंभ में आने वाली भीड़ की तस्वीरों से लोगों का अंदाजा लगाना मुश्किल है. ऐसे में सटीक अनुमान के लिए अकबेस्ड हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, वो 360 डिग्री कैमरे हैं. इस तरह के कैमरे पूरे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिनमें 1100 फिक्स्ड कैमरे हैं और करीब 744 अस्थाई कैमरे हैं. पूरे मिला क्षेत्र में लगे इन कैमरों के जरिए ही क्राउड की गिनती की जा रही है. साथ ही ड्रोन कैमरे डेंसिटी प्रति स्क्वायर मीटर को आंकते हैं और कुल एरिया के हिसाब से लोगों को कैलकुलेट करते हैं.

इसके अलावा भी अन्य तरीकों से भीड़ की गिनती की जा रही है. एक है पीपल फ्लो... कितने लोग जो किसी रूट से आ रहे हैं और मेला क्षेत्र में प्रवेश करने पर उनको गिना जा रहा है. किसी एरिया में क्राउड डेंसिटी क्या है जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो क्रिटिकल एरियाज है, उन पर भीड़ का घनत्व कितना है, वो इन कैमरों के माध्यम से आंका जा रहा है. इसके अलावा एक ऐप के जरिए लोगों के पास मौजूद मोबाइल फोन के औसत आंकड़े की गिनती की जा रही है. सभी डेटा क्राउड असेसमेंट टीम को भेजा जा रहा है, जो लोगों की गिनती के फाइनल आंकड़े मुहैया करा रही है.

सैटेलाइट की मदद से श्रद्धालुओं का डेटा

इसके पहले कुंभ आने वाली ट्रेन, बसों और नावों की गिनती के आधार पर लोगों का डेटा जमा किया जाता था. साथ ही मेला क्षेत्र में बने हुए साधु-संतों के शिवरों में आने वाले लोगों का आंकड़ा जुटाकर उनकी गिनती की जाती है. यही नहीं, शहर की सड़कों पर मौजूद भीड़ का डेटा जमा करके भी लोगों की गिनती की जाती है. हालांकि इस बार भी ट्रेन और बसों की संख्या को ट्रैक किया जा रहा है.

साल 2013 यानी पिछले कुंभ से पहले तक लोगों की गिनती प्रशासन की ओर से जारी रिपोर्ट से होती थी और अधिकारियों की ओर से जारी डेटा को ही फाइनल माना जाता था. लेकिन अब इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर तकनीक की मदद ली जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सटीक आंकड़े जुटाए जा सकें. पहले सैटेलाइट के जरिए भी कुंभ में आने वाले लोगों को गिना जाता था, लेकिन उसकी खामी यह थी कि एक ही व्यक्ति अगर बार-बार मेला क्षेत्र में आया तो हर बार उसकी गिनती कर ली जाती थी, ऐसे में आंकड़े सटीक नहीं जुट पाते थे.

पहले हेड काउंट से होती थी गणना

जानकारी के मुताबिक 19वीं सदी से कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने का चलन शुरू हुआ था. अंग्रेजी हुकूमत में तो कुंभ की ओर आने वाले अलग-अलग रास्तों पर बैरिकेड लगाकर एक-एक कर लोगों की गिनती की जाती थी. साथ ही कुंभ आने वाले ट्रेनों की टिकटों की गिनती करके भी भीड़ का अनुमान लगाया जाता था. लेकिन तब भीड़ लाखों की संख्या में आती थी जो अब करोड़ों में तब्दील हो चुकी है. ऐसे में गणना के तरीके भी समय के साथ आधुनिक बनाए गए हैं.

हालांकि फिर भी जो भी आंकड़े आते हैं, वह एकदम सटीक हों, ये कह पाना मुश्किल ही होता है. फेस स्कैन के जरिए किसी व्यक्ति की रिपीट काउंटिंग से भले ही बचा जा सकता हो, फिर भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का एकदम सटीक डेटा जुटाना लगभग नामुमकिन है. यही वजह है कि तकनीक का सहारा लेकर कुंभ आने वाले लोगों का एक अनुमान ही लगाया जा सकता है.

3 कठिन परीक्षाओं को करना पड़ता है पार तब बनता है एक अघोरी

महाकुंभ में अघोरी और नागा साधु दोनों पहुंच चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि उन तीन कठिन परीक्षाओं के बारे में जो पास करने के बाद एक व्यक्ति अघोरी बनता है।

अघोरी

हिंदू धर्म में अघोरी साधुओं को नागा साधुओं से भी बेहद खतरनाक माना गया है। अघोरी साधु जीवन और मृत्यु के बंधनों से दूर श्मशान भूमि में अपनी धूनि रमाए तप में लीन रहते हैं। माना जाता है कि अघोरी साधु तंत्र साधना भी करते हैं। एक अघोरी बनने की प्रक्रिया को बेहद कठिन माना गया है। इस दौरान अघोरी साधु बनने की लालसा वाले व्यक्ति को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अंतिम परीक्षा में तो जान तक को दांव लगाना पड़ जाता है। अगर इन परीक्षाओं में कोई विफल हो जाए तो वह अघोरी नहीं बन पाता। ऐसे में आइए जानते हैं वह कौन-कौन सी परीक्षाएं हैं...

अघोरी बनना बेहद कठिन होता है। माना जाता है कि अघोरी शव पर एक पैर रख तपस्या करते हैं। ये भोले नाथ के उपासक माने जाते हैं। साथ ही ये मां काली की भी पूजा करते हैं। अघोरी बनने की प्रक्रिया कठिन है, इसमें 3 तरह की दीक्षाएं शामिल हैं- हरित

अनादि शुक्ल

दीक्षा, शिरीन दीक्षा और रंभत दीक्षा

हरित दीक्षा

हरिता दीक्षा में ही अघोरी गुरु अपने शिष्य को गुरुमंत्र देता है। यह मंत्र शिष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। शिष्य को इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना होता है। इस जाप से शिष्य के मन-मस्तिष्क में एकाग्रता बनती है और वह आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल करता है।

शिरीन दीक्षा

शिरीन दीक्षा में सीखने वाले शिष्य को कई प्रकार की तंत्र साधना सिखाई जाती है। शिष्य को श्मशान भूमि में जाकर तपस्या करनी होती है। इस दौरान शिष्य को सांप, बिच्छू आदि का भय तो रहता ही है, साथ ही सर्दी, गर्मी, बारिश भी बर्दाश्त करनी होती है।

रंभत दीक्षा

रंभत दीक्षा अघोरी साधु के लिए सबसे कठिन और अंतिम दीक्षा होती है। इस दीक्षा में शिष्य को अपने जीवन और मृत्यु का अधिकार अपने गुरु को सौंपना होता है। गुरु जो भी कहे शिष्य को बिना सोचे या प्रश्न के वह करना ही पड़ता है। कहा जाता है कि इस दीक्षा में गुरु अपने शिष्य के अंदर भरे अहंकार को बाहर निकलवा देता है। इस दौरान अगर गुरु कहे कि अपने गर्दन पर चाकू रखना है तो शिष्य को बिना कोई सवाल के करना पड़ता है। इसलिए इस दीक्षा को बेहद कठिन माना जाता है। यही कारण है कि इन्हें अपनी जिंदगी या मौत का कोई भय नहीं रहता क्योंकि अघोरी अपने गुरु को इसका अधिकार दे देते हैं।

महाकुम्भ मेला

आध्यात्मिक एवं आर्थिक महत्व

प्रवीण चौधरी

कुम्भ मूल शब्द कुम्भक (अमृत का पवित्र घड़ा) से आया है। ऋग्वेद में कुम्भ और उससे जुड़े स्नान अष्ठान का उल्लेख है। इसमें इस अवधि के दौरान संगम में स्नान करने से लाभ, नकारात्मक प्रभावों के उन्मूलन तथा मन और आत्मा के कायाकल्प की बात कही गई है।

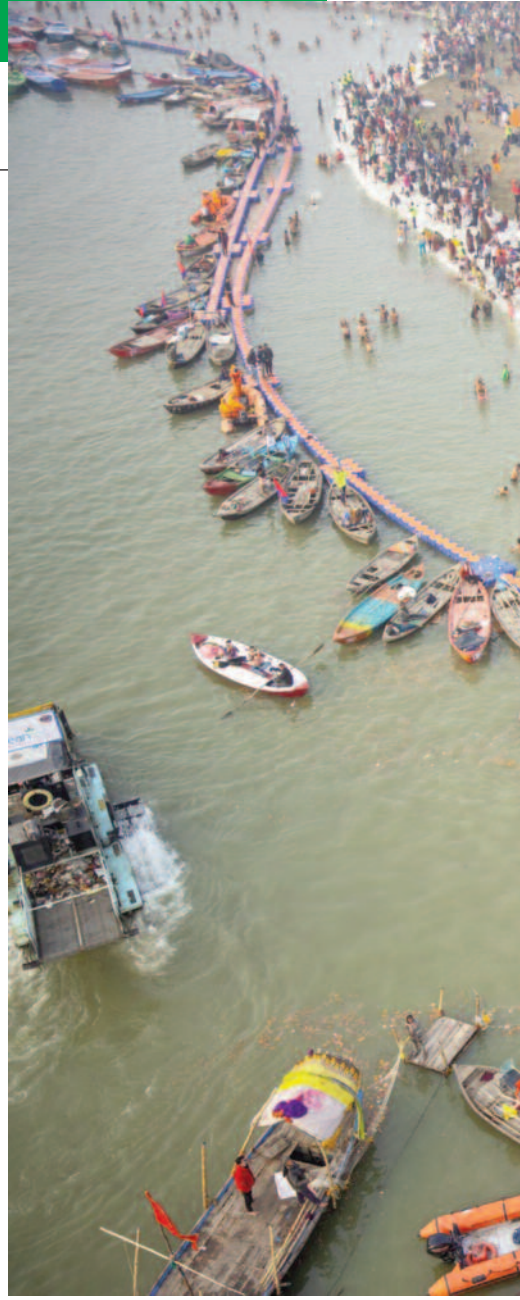

हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार कुंभ मेला एक धार्मिक महाआयोजन है जो 12 वर्षों के दौरान चार बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में चार स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल चार पवित्र नदियों पर स्थित चार तीर्थस्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है, यथा, (1) हरिद्वार, उत्तराखंड में, गंगा के तट पर; (2) मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर; (3) नासिक, महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर; एवं (4) उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर।

प्रत्येक स्थल का उत्सव, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक-सांस्कृतिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है।

कुम्भ मूल शब्द कुम्भक (अमृत का पवित्र घड़ा) से आया है। ऋग्वेद में कुम्भ और उससे जुड़े स्नान अष्ठान का उल्लेख है। इसमें इस अवधि के दौरान संगम में स्नान करने से लाभ, नकारात्मक प्रभावों के उन्मूलन तथा मन और आत्मा के कायाकल्प की बात कही गई है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी कुम्भ के लिए प्रार्थना लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत के पवित्र घड़े (कुम्भ) को लेकर युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर कुम्भ को लालची राक्षसों के चंगुल से छुड़ाया था। जब वह इस स्वर्ग की ओर लेकर भागे तो अमृत की कुछ बूंदे चार पवित्र स्थलों पर गिरीं जिन्हें हम आज हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इन्हीं चार स्थलों पर प्रत्येक तीन वर्ष पर बारी बारी से कुम्भ मेले का आयोजन किया जाता है।

कुम्भ मेला दुनिया में कहीं भी होने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं। मुख्य रूप से इस समागन में तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं।

कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं

और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं, संन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं, अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं।

कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं; हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे 'पेशवाई' कहा जाता है, 'शाही स्नान' के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में, तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां, जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं।

महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी, 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। यह एक हिंदू त्यौहार है, जो मानवता का एक स्थान पर एकत्र होना भी है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले में दुनिया भर से 15 करोड़ पर्यटक आए थे। यह संख्या 100 देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। यह वास्तव में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध है।

कुंभ मेला कई शताब्दियों से मनाया जाता है। प्रयागराज कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख वर्ष 1600 ई. में मिलता है और अन्य स्थानों पर, कुंभ मेला 14वीं शताब्दी की शुरूआत में आयोजित किया गया था। कुंभ मेला बेहद पवित्र और धार्मिक मेला है और भारत के साधुओं और संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। वे वास्तव में पवित्र नदी के जल में स्नान करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। अन्य लोग इन साधुओं के शाही स्नान के बाद ही नदी में स्नान कर सकते हैं। वे अखाड़ों से संबंधित हैं और कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आते हैं। घाटों की ओर जाते समय जब वे भजन, प्रार्थना और मंत्र गाते हैं, तो उनका जुलूस देखने लायक होता है।

कुंभ मेला प्रयागराज 2025 पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होता है, जो 13 जनवरी 2025 को है और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। यह पर्यटकों के लिए भी जीवन में एक बार आने वाला अनुभव है। टेंट और कैंप में रहना आपको एक गर्मजोशी भरा एहसास देता है और रात में तारों से भरे आसमान को देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है।

कुंभ मेले में सत्संग, प्रार्थना, आध्यात्मिक व्याख्यान, लंगर भोजन का आनंद सभी उठा सकते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में गंगा नदी में पवित्र स्नान, नागा साधु और उनके अखाड़े से मिलें। बेशक, यह कुंभ मेले का नंबर एक आकर्षण है। कुंभ मेले के दौरान अन्य आकर्षण प्रयागराज में घूमने लायक जगहें हैं जैसे संगम, हनुमान मंदिर, प्रयागराज किला, अक्षयवट और कई अन्य। वाराणसी भी प्रयागराज के करीब है और हर पर्यटक के यात्रा कार्यक्रम में वाराणसी जाना भी शामिल है।

प्रशासनिक अनुभव की समृद्ध पृष्ठभूमि से गाजियाबाद को नई दिशा देंगे नये

जिलाधिकारी दीपक मीणा

ललित कुमार

गाजियाबाद के नये जिलाधिकारी के रुप में दीपक मीणा जनपदवासियों को राहत देने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। वर्ष 2011 बैच के आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी दीपक मीणा इससे पहले मेरठ में जिलाधिकारी थे और वहां उनका कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। माना जा रहा है कि प्रशासनिक अनुभव की समृद्ध पृष्ठभूमि के चलते जिलाधिकारी दीपक मीणा गाजियाबाद को नई दिशा देने का काम करेंगे।

19 दिसम्बर को दीपक मीणा ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पहले उन्हें जिला मुख्यालय पहुंचने पर गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके उपरांत उन्होंने ट्रेजरी पहुंचकर चार्ज लिया। उन्होंने कहा कि वे गाजियाबाद जनपद की समस्याएओं को समझकर उन्हें पहली प्राथमिकता से हल कराएंगे। हर जनरद की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। ऐसे में गाजियाबाद की मुख्य समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाई जाएगी।

इसके साथ ही शासन की ओर से लागू जनहित की योजनाओं का पात्र व्यक्तियों तक अधिकतम लाभांवित करना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं। उनका हर संभव प्रयास हो गा कि जनपदवासियों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाकर उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जा सकें।

उत्तर प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन, विकास व अन्य परियोजनाओं को समय से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर यथाशीघ्र जनता को उससे लाभांवित कराना भी उनकी प्राथमिकता में रहेगा। डीएम दीपक मीणा ने कहा कि वे मीडियाफ्रैंडली है और जनहित के लिए वे पत्रकारों व अन्य मीडिया प्लेटफार्मो पर दिये गये उपयोगी सुझावों को अमल में लाने का प्रयास करेंगे। मीडियो से फीडबैक लेकर सरकारी योजनाओं को और बेहतर तरीके क्रियान्वयन करने व लाभार्थियों तक उसका लाभ पहुंचाने में मद्द मिलती है।

नवनियुक्त जिलाधिकारी का कहना है कि वे शासन की मशा के अनुरूप कार्य किए जाएंगे। जो परियोजनाएं लंबित हैं, उन्हें पूरा कराने में तेजी लाई जाएगी ताकि अनावश्यक देर ने हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने गाजियाबाद को चुनौती पूर्ण जिला माना है। इससे उन्हें अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनवाने में मदद मिलेगी।

गाजियाबाद के नये जिलाधिकारी दीपक मीणा का जीवन परिचय

दीपक मीणा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। वे 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 15 जुलाई 1986 को जन्मे दीपक मीणा को 14 अप्रैल 2022 को योगी सरकार ने मेरठ का डीएम नियुक्त किया था। शासकीय स्तर पर रुटीन तबादला नीति के तहत वे 19 जनवरी, 2025 को गाजियाबाद के डीएम बनाये गये। मेरठ में जिलाधिकारी रहने से पूर्व वे सिद्धार्थनगर के डीएम और उससे पहले श्रावस्ती के जिलाधिकारी रह चुके हैं।

जिलाधिकारी पद के जिम्मेदारी संभालने से पहले वे अपनी भारतीय प्रशासनिक सेवा के शुरूआत दीपक मीणा की पहली पोस्टिंग अलीगढ़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रुप में हुई थी। अलीगढ़ के बाद उनका स्थानांतरण आजमगढ़ के लिए किया गया। आजमगढ में भी उन्हें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद भेजा गया था। दीपक मीणा की पहली पोस्टिंग अलीगढ़ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रुप में हुई थी। अलीगढ के बाद उनका स्थानांतरण आजमगढ़ के लिए किया गया। आजमगढ में भी उन्हें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद भेजा गया था। वे 2014 में प्रोन्नत करके सीडीओ बुलंदशहर बनाये गये। इसके बाद आगरा, सहारनपुर, मैनपुरी और अलीगढ़ में बतौर सीडीओ तैनात रहे हैं। वे 2017 से 2019 तक डीएम श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में डीएम रहे। सिद्धार्थ नगर के डीएम पद रहते हुए जनपद में विकास योजना में बेहतर काम करने पर दीपक मीणा को प्रधानमंत्री द्वारा अवॉर्ड भी दिया गया था।

आईआईटी खड़गपुर से बीटेक हैं दीपक मीणा

दीपक मीणा आईआईयिन हैं। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की है। बीटेक करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में नौकरी मिल गयी थी, लेकिन फिर उनमें प्रशासनिक सेवा में जाने का चाह बलवती हुई तो नौकरी से साथ-साथ उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। कड़ी मेहनत के बल पर वर्ष 2010 की यूपीएससी परीक्षा में उनका चयन आईएएस के लिए हो गया। इसके बाद मसूरी आईएएस अकादमी में मई 2012 तक उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और इसके बाद उन्हें यूपी कैडर अलॉट किया गया था।

इंजीनियर से आईएएस बने अतुल वत्स की कार्यशैली का हर वर्ग कायल

इंद्रेश शर्मा

मार्च, 2024 से जीडीए उपाध्यक्ष के रुप में विकास के क्षेत्र में निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका

उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 2024 को इंजीनियर से आईएएस बने अतुल वत्स को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए वीसी) का उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा था। तब करीब छह साल के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष मिला था। अतुल वत्स के कार्यकाल में प्राधिकरण विकास कार्यों में नित्य नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वे अपनी विशिष्ट कार्यशैली से शहर के विकास में चार चांद लगाकर गाजियाबाद को एक अलग ही पहचान दिलवाने में लगे हुए हैं।

अतुल वत्स दूसरी बार किसी विकास प्राधिकरण में बतौर उपाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं। यहां की तैनाती से पहले वे अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। वहीं से स्थानांतरण करके अतुल वत्स को जीडीए का वीसी बनाया गया था। मिल जाने से लोगों के रुके हुए कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दायित्व छह साल का यहां तैनात रहे जिलाधिकारियों के पास ही रहा था, लेकिन जब से वे पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष बनाये गये शहर में विकास योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी जाने लगीं हैं और महानगर में चहुंमुखी विकास होना दिख रहा है।

बता दें कि अतुल वत्स मूल रुप से हरियाणा के बहादुरगढ़ जनपद में स्थित कुलासी गांव के

रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में वर्तमान समय में इनका परिवार सोनीपत (हरियाणा)में निवासी करता है। इनके पिता सतीश कुमार आर्मी से रिटायर्ड हैं और उन्हें कारगिल युद्ध के दौरान अपना शौर्य दिखाने का अवसर मिला था।

हरियाणा में जन्में अतुल वत्स की प्राथमिक शिक्षा वहां के ही एक सैनिक स्कूल से हुई है। वे पढाई में काफी होशियार थे.। उन्होंने 12वीं कक्षा में 92% अंक हासिल किए थे। इसके बाद चंडीगढ़ से उन्होंने इंजीनियरिंग यानी बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आम युवकों की तरह अतुल वत्स ने जिंदल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी की। लेकिन बाद में पिता के प्रोत्साहन पर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय लिया।

वर्ष 2014 में नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर उन्होंने बिनाकोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा दी और वर्ष 2015 में सिविल सर्विस परीक्षा में 60वीं रैंक हासिल की थी। उनका पहला चयन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में हुआ था। एक आईएएस अधिकारी के रुप में अपने दायित्वों को लेकर वे काफी सख्त माने जाते हैं। किसी भी कार्य में कनिष्कों द्वारा किसी भी किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं हैं। यही वजह है कि दस ग्यारह महीने का कार्यकाल में ही उन्होंने कई उपलब्यिां अपने नाम की हैं।

इन्दिरापुरम योजना का हस्तांरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के तौर पर अतुल वत्स के नेतृत्व में वर्ष-2024 में कई उल्लेखनीय कार्य किये गये। इस दौरान उन्होंने नया गाजियाबाद व हरनन्दीपुरम योजना लाये जाने की संकल्पना का क्रियान्वित किया। इस योजना की परिधि का निर्धारण करके कुल 521 हेक्टेअर भूमि पर योजना के लिए चिन्हित की गई।

इसके अलावा उन्हीं के प्रयासों से वर्षों से लंबित इन्दिरापुरम योजना को नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरित किया गया है। इसके लिये आवश्यक नागरिक सुविधाओं के उपयोग हेतु प्राधिकरण द्वारा रुपए 185 करोड़ नगर निगम गाजियाबाद की दिये गये। यह कार्य विकास की दृष्टि से सुचारू प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का कार्यान्वयन

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक

दिसम्बर 2024 से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा चुका है। इससे प्रशासनिक कार्यशैली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया गया है। इसके क्रियान्वयन से प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारियों को प्रातः 10 बजे से 10.15 तक अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन पर दर्ज कराना आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी 10.30 बजे के बाद उपस्थिति दर्ज करता है तो उसका आकस्मिक अवकाश एवं वेतन आहरण पर प्रतिबंध किये जाने के लिए उनके द्वारा आदेश जारी कर दिये जाते हैं।

लैण्ड ऑडिट व सम्पत्ति ऑडिट

प्राधिकरण की पूर्व विकसित योजनाओं का लैण्ड ऑडिट और सम्पत्ति ऑडिट विशेषज्ञ फर्म के माध्यम से कराया गया। इस प्रक्रिया में विभिन्न योजनाओं में से लगभग 1000 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति रिक्त पायी गई, जिसे नियोजित कर नीलामी के माध्यम से निस्तारण कराया जा रहा है।

मधुबन बापूधाम योजना में गतिरोध का समाधान

प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2008 में प्रकाशित करायी गई मधुबन बापूधाम योजना में चल रहे किसान व भूधारकों के गतिरोध को समाप्त करने की रणनीति बनायी गई। इसमें किसानों को न्यायालय द्वारा निर्धारित विकसित भूखण्ड की मांग की जा रही थी। इस मांग के क्रम में 06 प्रतिशत व 10 प्रतिशत के अनुपात में भूखण्ड सृजित कर दिये गये हैं, जिनका आगे आवंटन उन्हें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जायेगा।

मलिन बस्ती/ईडब्लूएस इकाईयों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्नियोजन

प्राधिकरण द्वारा तुलसी निकेतन योजना के ईडब्लूएस भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कंसलटेंट एजेंसी ईएण्डवाई से कार्ययोजना व डीपीआर तैयार करायी जा रही है। भविष्य में पीपीई मॉडल पर मजबूत व शानदार भवन, दुर्बल वर्ग/अल्प आय वर्ग के लोगों को दिये जायेंगे।

विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन

जीडीए के अधिकारियों/कर्मचारियों को दक्ष करने के लिये विभिन्न प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें मुख्य रुप से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं आईजीआरएस के संबंध में सितंबर -2024 को कार्यशाला का आयोजित हुई। वित्त एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियाकलापों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 दिसंबर से 18 दिसंबर 2024 तक आयोजित

किया गया।

इस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (ईओआरसी) प्रोजेक्ट की संकल्पना

इस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (ईओआरसी) प्रोजेक्ट की संकल्पना भारत में एक समर्पित रेलवे मार्ग तैयार करने से जुड़ी है। यह मुख्यतः आर्थिक, औद्योगिक और पर्यावर्णीय उद्देश्यों के पूरा करने के लिये प्रस्तावित है। यह कॉरिडोर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और उसके आसपास के राज्यों में यातायात का दवाब कम करने, औद्योगिक क्षेत्र को आपस में जोड़ने और माल परिवहन को अधिक तेज और कुशल बनाने पर केन्द्रित है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एवं संकल्पना माल परिवहन में वृद्धि, यातायात दवाब कम करना, औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ना, पर्यावर्णीय लाभ, आर्थिक विकास व अन्य है। यह परियोजना लॉजिस्टिक सेक्टर में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है।

आमजन मानस के लिए किये गये अन्य कार्य

प्राधिकरण ने 406 नग यू-टर्न राजनगर एक्सटेंशन में बनाने का कार्य, पार्कों की सुदृढ़ीकरण का कार्य, थीम पार्क हेतु दो पार्कों का चयन, हाथी पार्क एवं नींबू पार्क, जल संरक्षण हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान, गंगोत्री टावर में 78 फ्लैटों को असामाजिक तत्वों से कब्जा मुक्त कर सील किया गया और ग्रीन पहल के अन्तर्गत इस सत्र में 1,30,092.00 पौधों का रोपण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न स्रोतों से प्राधिकरण हो हुई आय का लेखा

प्रवर्तन जोनों से शमन शुल्क की मद में लगभग	रुपए 22.75 करोड़
नियोजन एवं मानचित्र स्वीकृति की मद में लगभग	रुपए 319.83 करोड़
सम्पत्ति के विक्रय आदि से रुपए लगभग	रुपए 288.07 करोड़
अन्य मद	रुपए 102.22 करोड
कुल आय	रुपए 732.87 करोड़

नये साल में प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्य

- हरनंदीपुरम योजना थीम पार्क का निर्माण,लैण्ड ऑडिट में प्राप्त लगभग 1000 करोड़ की सम्पत्तियों के निस्तारण का कार्य।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न स्रोतों से प्राधिकरण हो हुई आय का लेखा

बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आईएएस अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक

वे टेनिस के उच्च स्तरीय खिलाड़ी होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के युवा होनहार वकील भी रहे हैं

नगरायुक्त के रुप में गाजियाबाद नगर निगम को नई पहचान देने में लेगे हैं विक्रमादित्य सिंह मलिक

सुदामा पाल

वर्ष 2018 बैच के आईएएस अधिकारी विक्रमादित्य सिंह मलिक को 19 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद में बतौर सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी के रुप में तैनाती मिली थी। वे करीब साढ़े 16 महीने तक सीडीओ के पर रहे और उन्होंने अपनी योग्यता व व्यवहारिक कार्यशैली से सबका दिल जीत लिया और प्रशासनिक अधिकारी के रुप में जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार तक अपनी अमिट कर्मठता व मेहनत की छाप छोड़ी।

इसी के चलते उन्हें करीब डेढ से भी कम समय की अवधि में सीडीओ के पद से स्थानांरित करके गाजियाबार नगर निगम में बतौर नगरायुक्त बनाया गया। तब से वे जनहित में लिये कठोर फैसले लेकर गाजियाबाद के विकास को नई पहचान व शक्ल देने में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ मामलों में मेयर सुनीता दयाल के साथ उनकी तल्खी भी देखने को मिली, लेकिन हमेशा सरकार की मंशा के अनुरुप काम

करने में विश्वास रखने वाले इस सब की परवाह किये बैगर अपने दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। कुछ जनप्रनिधि भले ही उनसे खुश न हों, लेकिन आम जनता के लिए वे मद्दगार आला अफसर हैं।

विक्रमादित्य सिंह मलिक मूल रूप से चंडीगढ़ निवासी हैं। उनकी बहन भी आईएएस अधिकारी हैं। टेनिस के उच्च स्तरीय खिलाड़ी होने के चलते उनकी चुस्ती देखते ही बनता है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में लॉ की मास्टर करने के दौरान वे क्रिकेट भी खेला करते थे, जबकि अपने स्कूल के दिनों में एक उच्च रैंक वाले टेनिस खिलाड़ी और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के दौरान उनकी एक पहचान स्क्वैश खिलाड़ी के रुप में भी थी।

वर्ष 2018 में आईएएस बनने से पहले वे

सुप्रीम कोर्ट के युवा होनहार वकील भी रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद स्थित नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से बीए एलएलबी (ऑनर्स) किया है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूके से कानून में मास्टर्स किया है। आईएएस बनने से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और कानून के क्षेत्र में कार्य किया है।

अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री होने के कारण उन्हें कानून अच्छी खासी जानकारी है, जिसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी प्रशासनिक दायित्व निभाने में भी करते हैं। कानून ने जानकार होने के कारण तकनीकी रुप में उनके अधीनस्थ उन्हें गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाते और यही कारण है कि अपने प्रशासनिक दायित्व वे पूरे उत्साह व रुचि से निभाते हैं। उनकी विशेष कार्यशैली ही उन्हें दूसरे अधिकारियों से अलग करती है और आम जनता में भी यही उनकी लोकप्रियता का कारण भी है।

विक्रमादित्य सिंह मलिक की पहली पोस्टिंग वाराणसी में वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी का प्रभारी के रुप में हुई थी। यहां तैनाती के दौरान उन्होंन कई बड़े पैमाने की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वे बिजनौर में संयुक्त

मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात रहे। इस दौरान उन्होंने अकेले ही बाइक्स ऑफ बिजनौर को अंजाम दिया, जो कचरे से धन बनाने वाला सार्वजनिक बाइक शेयरिंग कार्यक्रम था। इसकी परिकल्पना और क्रियान्वयन कोविड-19 की पहली लहर के दौरान प्रवासी श्रमिकों की लावारिस बाइकों का उपयोग करके किया गया था,जिसकी बहुत प्रशंसा की गयी थी। यदि आईएएस विक्रमादित्य सिंह मलिक के बचपन की बात करें तो स्कूली शिक्षा को दौरान विक्रमादित्य सिंह को लॉन टेनिस बहुत पसंद था। लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कुछ सालों तक उनका खेलों से रिश्ता टूट गया था, लेकिन अब फिल से वे अपने खेल के शौक के जीवित किये हुए हैं। खेलों को वे शारारिक फिटनेस के लिए भी जरुरी बताते हैं। साथ ही खेलने से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क भी रहता है और इससे उन्हें स्ट्रेस भी नहीं होता।

विक्रमादित्य मलिक की पारिवारिक पृष्ठभूमि

विक्रमादित्य सिंह मलिक पंजाब के चंडीगढ़ में जन्में हैं। उनके पिता युद्धवीर सिंह मलिक हरियाणा में आईएएस अधिकारी रहे हैं। इनकी बहन भी आईएएस अधिकारी हैं। वहीं इनकी माता दी एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं। शुरू से ही विक्रम पढ़ाई और खेल में अच्छे रहे। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान उन्हें अच्छे अंक मिले थे। आईएएस

बनने से पहले उन्होंने एक लॉ की कंपनी में भी काम किया था।

साल 2012 का जब इनकी बहन का चयन आईएएस अधिकारी के रुप में हो गया तो इन्हें भी आईएएस बनने की प्रेरणा मिली और फिर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी थी। वे अपने पहले दो बार प्रयासों में यूपीएससी परीक्षा पास नही सके थे, लेकिन निराशा को हौंसले में तब्दील कर साल 2017 में उन्होने यूपीएससी परीक्षा क्रैक करके देश में 48वीं रैंक हासिल की और सीधे आईएएस अधिकारी बन गए।

वर्तमान में गाजियाबाद के नगरायुक्त के रुप में शहर को नई दिशा देने की दिशा में रह रोज नये-नये प्रयोग व योजनाओं शुरु करके अपनी काबलियत का लोहा मनवा रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम के नगरायुक्त के तौर पर उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर जिक्र किया जाये उसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, लीगल केस मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट्स एंड बजट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम और म्यूटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम और म्यूटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम,रेंटेड मैनेजमेंट सिस्टम आदि मुख्य हैं। ये सभी सिस्टम शहर वासियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। इनके माध्यम से जहां नामांतरण की कार्यवाही सरल हो रही है, वहीं ऑनलाइन कार्यवाही करते हुए अपने कार्य का स्टेटस भी शहर वासी जान सकेंगे।

यूजर चार्ज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यूजर चार्ज जो कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन सेवाओं के बदले उपभोक्ताओं से लिया जाता है। जिसको ऑनलाइन जमा करने की सुविधा नगर निगम ने इस पोर्टल के माध्यम से शुरू की है और इसका जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है।

डीसीपी राजेश कुमार की कार्यशैली अपराधियों में खौफ

प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस राजेश कुमार ने पिछले वर्ष जुलाई में गाजियाबाद के डीसीपी सिटी के तौर पर चार्ज संभाला था, तब से ही महानगर क्षेत्र के अपराधियों में उनका खौफ छाया हुआ है। उन्होंने जिस तरह से शहर क्षेत्र में खुले में शराब पीने वालों पर शिकंजा कसा है और स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी की अनैतिक धंधा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, तब से इस गैर कानून कामों में लिप्त लोगों की नींद उड़ी हुई है। उनकी सख्ती का प्रभाव यह है कि महानगर के तमाम होटलों में अब मौज मस्ती करने के लिए जाने वाले जोड़ों ने भी तौबा करते नजर आते हैं।

डीसीपी सिटी के तौर पर आईपीएस राजेश कुमार खासे चर्चा में रहते हैं। वे गाजियाबाद की भौगोलिक स्थिति और यहां के लोगों की कमियों व

ललित कुमार

खूबियों से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इस कारण यह है कि राजेश कुमार पूर्व में गाजियाबाद में बतौर एसपी ट्रैफिक तैनात रह चुके हैं। वे आसपास की भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि वे गाजियाबाद के निकटतम जनपद मेरठ के साथ-साथ सहारनपुर और फिरोजाबाद में एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण के रूप में सेवा दे चुके हैं। गाजियाबाद में दी गई तैनाती से पहले वे लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण विभाग में एसपी के पद पर कार्यरत थे। योगी सरकार ने उनकी योग्यता व कार्यक्षमता को देखकर ही उन्हें गाजियाबाद डीसीपी के पद पर भेजा गया था और जिस उम्मीद से उन्हें यहां भेजा गया था, उस पर वे पूरी तरह से खरा उतर रहे हैं।

आईपीएस राजेश कुमार वर्ष आईपीएस-एसपीएस 2015 के आईपीएस हैं। उनका गृह जनपद जौनपुर, उत्तर प्रदेश है और उन्होंने एम.ए.(दर्शनशास्त्र) में किया। उन्हें 15 अगस्त 2022 को पुलिस सेवा वसेवा अलंकरण उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा जा चुका है, इसके बाद 26 जनवरी, 2023 को महानिदेशक की प्रशस्ति डिस्क सिल्वर से सम्मानित कर चुके हैं।

इस समय डीसीपी नगर राजेश कुमार सिंह ने सार्वजनिक स्थलों पर खड़े होकर शराब पीने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर खासी चर्चा में हैं। हाल ही में उनके नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों

पर शराब पीने के मामलों की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान चलायी गयी। पुलिस ने ढाई घंटे के अंदर 274 लोगों को खुले में शराब पीते हुए पकड़ लिया। पुलिस उनको हिरासत में लेकर थाने ले गई और उन सबके उनके खिलाफ धारा-34 के अंतर्गत चालान किया। इससे काफी हद तक गाजियाबाद में खुले में खराब पीना बंद हो गया है।

इस संबंध में डीसीपी नगर राजेश कुमार सिंह का कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर खड़े होकर शराब पीने की घटनाओं से आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। आमतौर पर कमिश्नरेट पुलिस शाम साढ़े सात बजे से पुलिस ने नगर क्षेत्र के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाती है। पुलिस की इस कार्रवाई से सड़क किनारे या बीच सड़क पर वाहन खड़ा करते हुए शराब पीते हुए मिलने पर उनसे पूछताछ की जाती है, ताकि किसी बेकसूर पर कार्रवाई न हो। यदि पुलिस को लगता है कि वह वास्तव में जानबूझकर खुले में मस्ती के लिए शराब पी रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जबकि अधिकांश को चेतावनी देकर मौके पर ही छोड़ दिया जाता है।

एक घटना के बारे में उन्होंने कहा कि आरडीसी में कार में बैठकर शराब पी रहे कविनगर के एक कारोबारी को जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने मुंह छिपा लिया। पुलिस ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो कहा कि साहब अब छोड़ दो। पकड़ा गया तो शहर भर में बहुत बेइज्जत हो जाऊंगा, आपसे वादा करता हूं कि आगे से खुले में क्या शराब ही छोड़ दूंगा। इस पर पुलिस ने उसे चेतावनी देकर

वहां से जाने दिया। ऐसे ही हमारे डीसीपी नगर राजेश कुमार सिंह की कार्यशैली जिसके सभी कायल हैं।

बता दें कि राजेश कुमार को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अबतक उन्होंने 82 एनकाउंटर किये हैं और 10 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया है। जिस जिले में भी वो तैनात थे उस जिले में एनकाउंटर ना हो, ऐसा नहीं हुआ है। इलाहाबाद में तैनाती के दौरान छह सिपाहियों की हत्या का बदला उन्होंने ही लिया था। वह 2007 में वहां तैनात थे। फिरोजाबाद में तैनाती के दौरान कुख्यात अपराधी दुर्गेश का बड़ा आतंक था उसको भी मुठभेड़ में मार गिराया था। मेरठ में भी एसपी देहात के पद पर रहते हुए कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया था। सहारनपुर में भी वो लंबे समय तक एसपी सिटी के पद पर तैनात रहे। गाजियाबाद से भी उनका पुराना अनुभव है। यही कारण है कि उन्हें गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण जनपद में तैनाती दी है। राजेश कुमार जोनपुर के रहने वाले हैं और उनके भाई भी आईएएस हैं। वह शिक्षित परिवार से हैं। उनके पिता भी प्रिंसिपल रहे हैं।

दिल्ली के कारोबारी से लूट करने वाले लुटेरे को किया था लंगड़ा

पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में 2024 के अक्टूबर माह में दिल्ली के कारोबारी से हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी राजेश कुमार ने बताया था कि 7 अक्टूबर को दिल्ली के पहाडगंज निवासी कारोबारी मनोज खंडेलवाल से बाइक सवार बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया था। पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की गई। उसी दौरान नंदग्राम एसएचओ धर्मपाल सिंह की टीम ने भट्टा नंबर पांच के पास से मुठभेड़ में मनीष शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा निवासी मकान नंबर 557 भटीपुरागढ रोड किठौर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया था। जिसके पास से लूट के चांदी के 168 छत्र और तमंचा बरामद किया था। डीसीपी ने बताया 7 अक्टूबर को लुटेरा मनीष दिल्ली में चांदनी चौक गया था, जहां उसने एक कारोबारी को बैग में चांदी भरकर स्कूटी पर ले जाते देखा गया था। उसकी बातचीत से इतना पता लग गया कि वह चांदी मेरठ में सप्लाई करने जा रहा था।

हाल ही में सम्पन्न हुए विवाहों के मौसम में भारतीय परिवारों द्वारा किए गए खर्च के चलते अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को गति मिलेगी जो द्वितीय तिमाही में गिरकर 5.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी।

विश्व में अपना विशेष स्थान बनाता भारत

अजीत शर्मा

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की दृष्टि से भारत की अपनी विशेषताएं हैं, जो अन्य देशों में नहीं दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए भारत में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों एवं मेलों आदि में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं द्वारा न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से इन मेलों/कार्यक्रमों में भाग लिया जाता है बल्कि इन श्रद्धालुओं द्वारा इन स्थानों पर किये जाने वाले खर्च से स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने एवं रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित करने में भी अपना योगदान दिया जाता है। इसी प्रकार, धार्मिक पर्यटन भी केवल भारत की विशेषता है। प्रतिवर्ष करोड़ों परिवार धार्मिक स्थलों पर, विशेष महुरतों पर, पूजा अर्चना करने के लिए इकट्ठा होते है। जम्मू में माता वैष्णोदेवी मंदिर, वाराणसी में भगवान भोलेनाथ मंदिर, अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर, उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर, दक्षिण में तिरुपति बालाजी मंदिर आदि ऐसे श्रद्धास्थल है जहां पूरे वर्ष भर ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होने वाले कुम्भ के मेले में भी करोड़ों की

संख्या में श्रद्धालु ईश्वर की पूजा अर्चना हेतु प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एवं उज्जैन में पहुंचते हैं। शीघ्र ही, 14 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में महाकुम्भ मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुम्भ की 44 दिनों की इस इस पूरी अवधि में प्रतिदिन एक करोड़ श्रद्धालुओं के भारत एवं अन्य देशों से प्रयागराज पहुंचने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है, इस प्रकार, कुल मिलाकर लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुगण उक्त 44 दिनों की अवधि में प्रयागराज पहुंचेंगे। करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले इन श्रद्धालुगणों द्वारा इन तीर्थस्थलों पर अच्छी खासी मात्रा में खर्च भी किया जाता है। जिससे विशेष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था को तो बल मिलता ही है, साथ ही करोड़ों की संख्या में देश में रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होते हैं एवं होटल उद्योग, यातायात उद्योग, पर्यटन से जुड़े व्यवसाय, स्थानीय स्तर के छोटे छोटे उद्योग एवं विभिन्न उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यापारियों के व्यवसाय में भी अतुलनीय वृद्धि होती दिखाई देती है।

इसी प्रकार, भारत में विवाहों के मौसम में सम्पन्न होने वाले विवाहों पर किए जाने वाले भारी भरकम खर्च से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। वर्ष 2024 के, मध्य नवम्बर से मध्य दिसम्बर के बीच, भारत में 50 लाख विवाह सम्पन्न हुए हैं। उक्त एक माह की अवधि के दौरान सम्पन्न हुए इन विवाहों पर भारतीय परिवारों द्वारा 7,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का खर्च किया गया है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में सम्पन्न हुए विवाहों पर 5,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का खर्च किया गया था। उक्त वर्णित 50 लाख विवाहों पर औसतन प्रति विवाह 14,000 डॉलर, अर्थात लगभग 13 लाख रुपए की राशि का खर्च किया गया है एवं 50,000 विवाहों पर तो एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि का खर्च किया गया है। भारत में प्रति विवाह होने वाला औसत खर्च, परिवार की औसत प्रतिवर्ष की कुल आय का तीन गुणा एवं देश में औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 5 गुणा के बराबर रहता है। भारत में विवाहों पर पूरे वर्ष में कुल 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च किया जाता है जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन में प्रतिवर्ष विवाहों पर 17,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का खर्च किया जाता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आगामी वर्ष में भारत, विवाहों पर किए जाने वाले खर्च की दृष्टि से, चीन को पीछे छोड़कर पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ विवाह सम्पन्न होते हैं। भारत में सर्दियों के मौसम को विवाहों का मौसम कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं क्योंकि पूरे वर्ष भर में सम्पन्न होने वाले विवाहों में से लगभग 50 प्रतिशत विवाह सर्दियों के मौसम में ही सम्पन्न होते हैं।

भारत में विवाहों पर होने वाले भारी भरकम राशि के कुल खर्च में से प्रीवेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, पोस्टवेडिंग फोटोग्राफी पर लगभग 10 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जाता है। विवाह के स्थान के चयन एवं साज सज्जा पर वर्ष 2023 में 18 प्रतिशत की राशि का खर्च किया गया था, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 26 प्रतिशत हो गया है क्योंकि भारतीय परिवारों द्वारा विवाह अब अन्य शहरों यथा गोवा, पुष्कर, उदयपुर एवं केरला जैसे स्थानों पर सम्पन्न किया जा रहे हैं। खानपान आदि पर कुल खर्च का लगभग 10 प्रतिशत भाग खर्च किया जा रहा है। म्यूजिक आदि पर लगभग 6 प्रतिशत की राशि का खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार, ज्वेलरी, ऑटो बाजार एवं सोशल मीडिया आदि पर भी अच्छी खासी राशि का खर्च किया जाता है। इससे, उक्त समस्त क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। अतः भारत में विवाहों के मौसम में होने वाले भारी भरकम राशि के खर्च से देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को तेज करने में सहायता मिलती है।

हाल ही में सम्पन्न हुए विवाहों के मौसम में भारतीय परिवारों द्वारा किए गए खर्च के चलते अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर को गति मिलेगी जो द्वितीय तिमाही में गिरकर 5.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी। विनिर्माण क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में विकास दर अधिक रहने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। बंग्लादेश में राजनैतिक अस्थिरता के चलते रेडीमेड गार्मेंट्स के क्षेत्र में विनिर्माण इकाईयां बंद हो रही हैं एवं वैश्विक स्तर पर रेडीमेड गर्मेंट्स के क्षेत्र में कार्यरत सप्लाई चैन की इकाईयां बांग्लादेश के स्थान पर अब भारत से निर्यात को प्रोत्साहित कर रही हैं। जिससे भारत में रेडीमेड गर्मेंट्स एवं फूटवीयर उद्योग में कार्यरत इकाईयों को इन उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने के ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं।

उक्त कारकों के चलते भारत में परचेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नवम्बर 2024 माह के 58.6 से बढ़कर वर्तमान में 60.7 हो गया है। इस इंडेक्स के ऊपर जाने का आश्य यह है कि विनिर्माण के क्षेत्र में गतिविधियों में गति आ रही है। इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी 6.21 प्रतिशत से घटकर 5.48 प्रतिशत पर नीचे आ गया है, अर्थात, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर भी नियंत्रण में आ रही है। जिससे आगे आने वाले समय में नागरिकों की खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होगी। हाल ही के वर्षों में विनिर्माण उद्योग, सेवा क्षेत्र एवं गिग अर्थव्यवस्था में रोजगार के करोड़ों नए अवसर निर्मित हुए हैं और वर्ष 2005 के बाद से इस वर्ष विभिन्न कम्पनियों द्वारा सबसे अधिक नई भर्तियां, रिकार्ड स्तर पर, की गई हैं। इस सबके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी 2025 माह में मोनेटरी पॉलिसी में रेपो दर में कमी किए जाने की प्रबल सम्भावना बनती दिखाई दे रही है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति की दर अब नियंत्रण में आ रही है। इस वर्ष भारत में मानसून का मौसम भी बहुत अच्छा रहा है एवं विभिन्न फसलों की बुआई रिकार्ड स्तर पर हुई है जिससे इन फसलों की पैदावार भी रिकार्ड स्तर पर होने की सम्भावना है। किसानों के हाथों में अधिक पैसा आएगा एवं उनके द्वारा विभिन्न उत्पादों की खरीद पर भी अधिक राशि का खर्च किया जाएगा। कुल मिलाकर, इन समस्त कारकों का सकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर होने जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी एवं चोथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के तेज रहने की प्रबल सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

'इंडिया' गठबंधन की कब्र पर खड़ा होगा तीसरा मोर्चा, लेकिन चलेगा कितने दिन?

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यदि क्षेत्रीय दल परस्पर एकजूट होकर तीसरा मोर्चा पुनः बना लेते हैं तो लोकसभा चुनाव 2029 की राजनीतिक लड़ाई भी त्रिकोणीय हो जाएगी। इससे जहां भाजपा फायदे में रहेगी, वहीं कांग्रेस को कुछ राज्यों में भारी चुनावी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।

एन के शर्मा

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जो राजनीतिक बयानबाजियां होती दिखाई दे रही हैं, उससे साफ है कि जहां 'इंडिया गठबंधन' अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, वहीं 'एनडीए गठबंधन' पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। इसके अलावा, एक खास लक्षण यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय राजनीति में कभी कद्दावर समझा जाने वाला कांग्रेस-भाजपा विरोधी तीसरा मोर्चा एक बार फिर से अपना नया आकार ग्रहण कर रहा है।

ऐसा इसलिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जहां अलग--थलग पड़ चुकी है, वहीं दिल्ली-पंजाब जैसे राज्यों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के पक्ष में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शरद पवार जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस विरोधी एकजुटता दिखा रहे हैं। इससे लोगों में यह संदेश जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सियासी लड़ाई सत्तारूढ़ पार्टी 'आप' और प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच ही होगी। जिसमें अभी तक आप का पलड़ा भारी है, क्योंकि वह सेक्यूलर और हिंदूवादी दोनों सियासी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है, जिससे चुनावी समां बंधती जा रही है।

वहीं, कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है जिससे धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय से जुड़े वोटों में बिखराव तय है। इससे आप को या तो भाजपा के हाथों सत्ता गंवानी पड़ सकती है, या फिर सूबे में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस के रहमोकरम पर निर्भर रहना पड़ सकता है। क्योंकि जब भी त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति आती है तो सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद यही वजह है कि सेक्यूलर सियासत करने के बावजूद आप हिंदूवादी मुद्दों को भी लपक रही है और हिंदुओं को फायदे पहुंचाने वाले फैसले कर रही है, ताकि जो हिन्दू भाजपा-कांग्रेस से नाराज हैं, वो आप की छतरी तले खुद को महफूज समझें। दरअसल, आप को आशंका है कि यदि राष्ट्रीय राजनीतिक ट्रेंड के मुताबिक मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में चले जायेंगे और उसकी प्रतिक्रिया में हिन्दू भाजपा की ओर चले जायेंगे तो उसे भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यदि क्षेत्रीय दल परस्पर एकजूट होकर तीसरा मोर्चा पुनः बना लेते हैं तो लोकसभा चुनाव 2029 की राजनीतिक

लड़ाई भी त्रिकोणीय हो जाएगी। इससे जहां भाजपा फायदे में रहेगी, वहीं कांग्रेस को कुछ राज्यों में भारी चुनावी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व को पता है कि अखिल भारतीय स्तर पर उनकी पार्टी ही भाजपा का मुकाबला कर सकती है, इसलिए देर सबेर क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को मानना पड़ेगा या फिर भाजपा के खेमे में जाना होगा।

दरअसल, कांग्रेस के नेतृत्व इंडिया गठबंधन बनने के बाद संयोजक के सवाल पर क्षेत्रीय दलों में जो सिरफुटौव्वल मची, उससे इसके सूत्रधार रहे जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुनः एनडीए की ओर लौटने के लिए विवश होना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों में सम्मानजनक सीट बंटवारे को लेकर जो चूहे-बिल्ली का खेल चला, यह बात भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नागवार गुजरी। तभी आप पार्टी ने हद कर दी थी। एक तरफ तो वह दिल्ली में कांग्रेस के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ रही थी, दूसरी तरफ पंजाब में दोस्ताना मुकाबले में कांग्रेस से बुरी तरह मात खाई और कांग्रेस से कम सीट ही जीत पाई। इसके अलावा, कांग्रेस के प्रभाव वाले प्रदेशों में समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, टीएमसी, एनसीपी शरद, शिवसेना यूबीटी आदि क्षेत्रीय दलों ने जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने की घुड़दौड़ शुरू की और कांग्रेस विरोधी बयानबाजियों का सहारा लिये, यह बात भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नागवार गुजरी। खासकर जम्मूकश्मीर विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जो क्षेत्रीय मुद्दे उठे, कांग्रेस के ऊपर बढ़त हासिल करने वाली कोशिशें हुईं, पारस्परिक टीका-टिपण्णी हुई और फिर ममता बनर्जी को आगे करके राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठाए गए, उससे यह तय हो गया कि राहुल गांधी के असली राजनीतिक दुश्मन भाजपा नहीं, बल्कि उनके इंडिया गठबंधन में ही मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को तवज्जो देना बंद कर दिया।

और तो और, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया (क्ठ.ऊकअ.) में दिख रही रार के बीच कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गत गुरुवार को दो टूक कह दिया कि, 'लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया (कठ.ऊकअ.) ब्लॉक का गठन किया गया था। कई राज्यों की स्थिति के आधार पर, चाहे वह कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल, वे स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं कि एक साथ लड़ना है या अलग-अलग।' इससे बौखलाए जम्मू-

कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर गठबंधन केवल संसदीय चुनाव के लिए था तो इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए।

दरअसल, उमर का पार्टी नैशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस और दूसरे दल यह तय करेंगे कि बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए। उन्होंने कहा, 'अगर गठबंधन विधानसभा चुनावों के लिए भी है तो हमें एक साथ बैठना होगा और सामूहिक रूप से काम करना होगा।' वहीं, उमर के बयान पर उनके पिता और ठउ अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भारत को मजबूत करने और नफरत को खत्म करने के बारे में है। गठबंधन स्थायी है। यह हर दिन और हर पल के लिए है।

इससे साफ है कि इंडिया गठबंधन रहे या नहीं रहे, इसको लेकर भी विपक्षी दल असमंजस में हैं। या फिर दो फाड़ हो चुके हैं, अपने-अपने सुविधा के मुताबिक। हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से मुकाबले के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में बने यूपीए, बिहार-यूपी में महागठबंधन और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सियासी हश्र से तो साफ है कि इंडिया गठबंधन का भी देर सबेर वही हश्र होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम 'इंडिया' कहते हैं तो देश के 'अभिजात्य वर्ग' का अहसास मिलता है। जबकि कांग्रेस ने हमेशा 'भारत' यानी गरीब-गुरुबों की राजनीति की है। लिहाजा, उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह यूपीए को जिंदा करके, जिसके मार्फत एक दशक तक देश पर राज कर चुकी है। वहीं, इंडिया को तिरोहित कर दे, क्योंकि इसने ही उसकी लोकसभा चुनाव 2024 की संभावनाओं पर तुषारापात कर दिया। ऐसा इसलिए कि भारतीय राजनीति में चाहे वामपंथी दल हों या समाजवादी दल या फिर दलितवादी दल, ये भरोसेमंद नहीं समझे जाते हैं। वहीं, ओबीसी की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल भी अपनी सियासी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। इनके नेतृत्व में बनने वाला तीसरा मोर्चा 1977, 1989, 1996 में केंद्रीय सत्ता में तो पहुंच गया, लेकिन 5 वर्ष भी अपनी सरकार नहीं चला पाया। क्योंकि इनके डीएनए में आपसी सिरफुटौव्वल है। तीनों बार इन्होंने महज 2-3 वर्षों के दौरान ही दो-दो प्रधानमंत्री दिए और मध्यावधि चुनाव का बोझ भी। इनके बारे में आम धारणा है कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जब ये एनडीए या यूपीए में होते हैं तो वहां भी उलटबांसी करते रहते हैं।

हां, राज्यों में इन्होंने 1967, 1977, 1989 और 1996 के सियासी बदलावों का फायदा उठाकर खुद को मजबूत किया। बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब आदि इसके सफल उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह बात अलग है कि भाजपा इनको निरंतर अप्रासंगिक किये जा रही है और एक के बाद दूसरा राज्य भी इनसे हड़पते जा रही है। कांग्रेस को भी चाहिए कि वह इन्हें ज्यादा तवज्जो न दे, खासकर चुनाव के पहले। क्योंकि कांग्रेस के वोटबैंक से ही ये खुद को मजबूत करते हैं और फिर उसी को आंख दिखाते हैं। इसलिए कांग्रेस को यदि लंबी राजनीति करनी है तो वह सूबाई और प्रमंडलीय नेतृत्व को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करे। वह विद्वानों और अंग्रेजी भाषी नेताओं से सलाह ले, लेकिन खाँटी राजनीतिक फैसले हिंदी भाषी या क्षेत्रीय भाषा-भाषी और जनाधार वाले नेताओं कहने पर करे, अन्यथा सभ्य शहरी सियासी दलाल उसकी कीमत पर खुद को मजबूत कर लेंगे और उसकी सियासी उद्धार नहीं होने देंगे।

कड़वा सच है कि 1977 से ब्रेक के बाद मैं यही ट्रेंड देख रहा हूँ। इसलिए अब से भी वह सम्भल जाए। इसके अलावा, सेक्यूलर बनने से ज्यादा व्यवहारिक बने। क्योंकि जबतक वह अल्पमतों को प्रभावित करने वाली राजनीति करेगी, उसे बहुमत कहाँ से मिलेगा, वह खुद सोचे-समझे-फैसले करे।

मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते अस्पताल

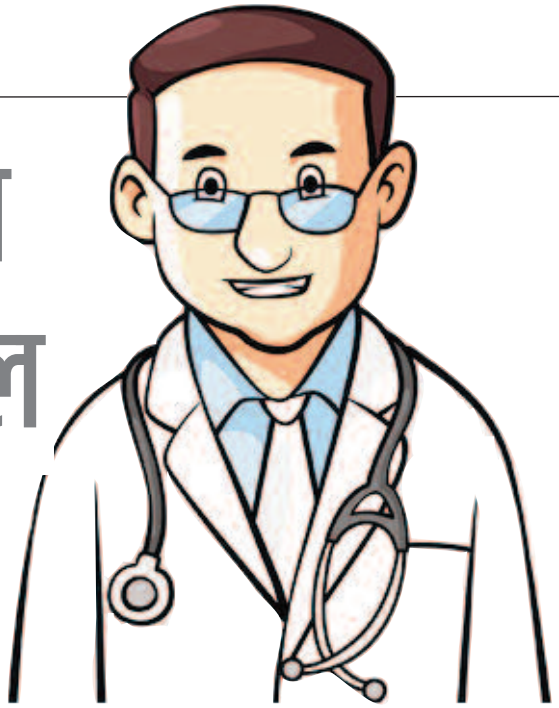

जानकारों के मुताबिक हृदय रोग में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेंट की मरीजों के लिए औसत मूल्य लगभग 2 लाख रुपए होती है. जबकि इसकी असल कीमत 10 से 15 हजार ही होती है.

अवकाश शर्मा

आज से करीब पैंतीस वर्ष पहले दिल्ली के एक पाँच सितारा होटल में नेत्र विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने बड़े शायराना अन्दाज में डॉक्टरों को सम्मान दिया. अपने भाषण में उन्होंने एक शेर सुनाया, ह्यतुमको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है किसको खुदा कहूँह्ल. पूरे हॉल में बज रही तालियों से यह बात स्पष्ट हो गई कि ज्ञानी जी जो संदेश देना चाहते थे वह सही जगह पहुँचा. दरअसल डॉक्टरों का सम्मान हर कोई इसी उम्मीद से करता है कि भगवान और माता-पिता के बाद यदि कोई पूजनीय है तो वह डॉक्टर भी हैं. परंतु यदि कुछ चुनिंदा और लालची डॉक्टर अपने पेशे से बेईमानी करने लगें तो लोगों का डॉक्टरों की पूरी जमात पर से ही विश्वास उठने लगेगा.

आये दिन हमें यह देखने को मिलता है कि जब किसी मरीज को इलाज के लिए किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है तो उसे काफी खर्च करना पड़ता है. हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएँ अभी इतनी बेहतर नहीं हुई है कि हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज कम से कम दर पर मिले. यदि आपके पास मेडिक्लेम न हो तो इलाज करवाना

आसान नहीं. परंतु मेडिक्लेम का नाम सुनते ही अस्पताल वाले आपसे अनाप-शनाप पैसे लेने लग जाते हैं. साथ ही आपके इलाज में जुटे डॉक्टर भी ऐसे तमाम टेस्ट आदि लिखवा देते हैं जिनकी शायद जरूरत ही न हो. बीमा कंपनियों और कुछ निजी अस्पतालों के द्वारा चल रहे ह्यमेडिक्लेमह्ल के गोरखधंधे के बारे में आये दिन शोर मचाता रहता है. क्या यह कहना सही नहीं होगा कि सेवा भाव से चलने वाले कुछ चैरिटेबल अस्पतालों को छोड़ कर कई नामी प्राइवेट अस्पताल मरीजों को केवल कमाई का जरिया ही मानते हैं?

कुछ समय पहले मुंबई के सात नामी अस्पतालों के खिलाफ ऐसा ही नाजायज बिलिंग और मरीजों से ठगी के मामले में केस दर्ज हुआ. इन अस्पतालों ने मरीजों से दवा पर छपे हुए दामों से कहीं अधिक रुपये वसूले. जब मामला जाँच एजेंसियों के पास पहुँचा तो सच सामने आया और इनके खिलाफ केस दर्ज हुए. जाँच में यह पाया गया कि जिस दर पर दवाइयाँ और अन्य सामग्री अस्पतालों को सप्लाई की जा रही थी, उसमें और मरीजों से लिये जाने वाली रकम में भारी अंतर था. इतना ही नहीं कई दवाओं और जरूरी सामग्री पर तो यह भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था कि इस विदेशी दवा या जरूरी वस्तु को किसने आयात किया और कब आयात किया. साथ ही इन पर मैन्यूफैक्चरिंग की तिथि भी नहीं छपी थी. इसके साथ ही कई दवाओं और वस्तुओं पर तो अधिकतम विक्रय दर (एमआरपी) भी नहीं छपा था. अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह मेडिकल वस्तुओं की बिक्री में ऐसा करना गैर-कानूनी है. परंतु शायद इन बड़े अस्पतालों के रसूख के चलते कोई आवाज नहीं उठाता या यदि कोई आवाज उठाए तो मामले की तह तक नहीं पहुँचने दिया जाता.

मेडीक्लेम वालों पर भर्ती होने का दबाव बनाते हैं

यदि मरीज के पास किसी भी तरह का स्वास्थ्य बीमा या मेडिक्लेम है तो आपको भर्ती होने के लिए दबाव डाला जाता है. केवल इसी दृष्टि से कि बिना भर्ती हुए आप मेडिक्लेम की कैशलेस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाएँगे. कैशलेस यानी कि मुफ़्त का इलाज. मुफ़्त के इलाज के लालच में मरीज और उसके तीमारदार भी अस्पताल के झाँसे में आ जाते हैं और बिना पढ़े कई सारे कागजों पर हस्ताक्षर भी कर देते हैं. फिर क्या, अस्पताल आपके साथ राजाओं की तरह का व्यवहार करता है. इस दिखावट की आड़ में अस्पताल ऐसे तमाम टेस्ट और जाँच शुरू कर देता है जिनकी इलाज की दृष्टि से जरा भी आवश्यकता नहीं होती. ऐसा केवल बीमा कंपनी को एक मोटा बिल भेजने की मंशा से किया जाता है। जब तक देश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तय मापदंड नहीं बनेंगे और उन्हें सख़्ती से लागू नहीं किया जाएगा तब-तब ऐसा होता रहेगा. सरकार को चाहिए कि हर इलाज के लिए मापदंडों को तय किया जाए और देश भर के सभी अस्पतालों में इलाज के मापदंड और उनकी दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए. इससे अज्ञानी मरीजों व उनके रिश्तेदारों को सभी तय नियम और मापदंड के बारे में पता रहेगा और साथ ही उनको इलाज के लिए कितना पैसा देना होगा उसकी भी जानकारी मिल सकेगी. यदि ऐसा होता है तो कभी भी कोई अस्पताल किसी की छोटी सी चोट के लिये प्लास्टिक सर्जरी करने की जुर्रत नहीं करेगा. इससे बीमा कंपनी की ठगी भी कम होगी, स्वास्थ्य सेवाएँ भी बेहतर होंगी और करदाता के पैसे की लूट भी बचेगी।

10 से 15 हजार ही होती है स्टेंट की कीमत

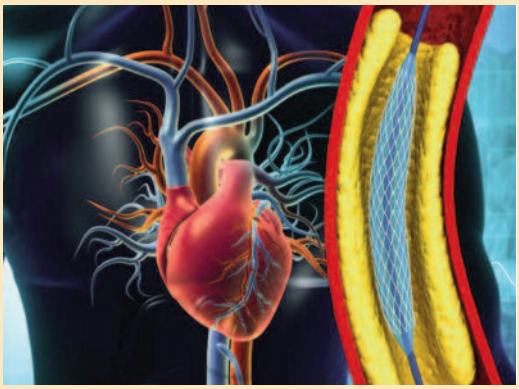

जानकारों के मुताबिक हृदय रोग में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेंट की मरीजों के लिए औसत मूल्य लगभग 2 लाख रुपए होती है. जबकि इसकी असल कीमत 10 से 15 हजार ही होती है. दरअसल इस स्टेंट को आयात करने वाला व्यक्ति इसे डिस्ट्रीब्यूटर को 40 हजार का बेचता है. अस्पताल को यह स्टेंट 80 से 90 हजार का मिलता है. अस्पताल इसे मरीज को 1.75 लाख से 2 लाख का बेचते हैं. जरा सोचिए जिस वस्तु की कीमत 10 से 15 हजार होती है और उसमें भी इसे बनाने वाले का मुनाफा शामिल है, उसे कई गुना दामों पर बेच कर न सिर्फ मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है बल्कि मरीजों की मजबूरी का भरपूर फायदा भी उठाया जा रहा है. इसलिए आज के युग में सभी को जागरूक और जानकार होने की जरूरत है.

नए भारत के निर्माण की मजबूत नींव

कपिल चौहान

बुनियादी ढांचा आर्थिक समृद्धि और राष्ट्र के समग्र विकास की पहचान होता है। बहुत सारे देश आर्थिक समृद्धि के लिये नई-नई योजनाओं पर काम करते हैं। जाहिर है कि भारत भी इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। बुजुर्गों से बात करने पर पता चलता है कि विकास योजनाओं के बल पर हमारा देश कितना-कुछ बदल चुका है। दूसरी ओर नई पीढ़ी से यह जानकारी मिलती है कि देश किस दिशा में चल रहा है और आने वाले वर्षों में भारत कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था व सामरिक ताकत वाला देश बनेगा?

बुनियादी ढांचे का विकास भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नए भारत को बनाने के लिये जिस तरह की बुनियाद रखने का प्रयास किया जा रहा, हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि भारत 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर साल 2047 तक 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला विकसित राष्ट्र बन सकता है। इसके लिये एक शर्त जरूर है कि इस अभियान में सबको साथ मिलकर चलना होगा और विकास व आर्थिक योजनाओं में ईमानदारी बरतनी होगी।

बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए रुपयों का देश के सकल घरेलू उत्पाद पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाजार के आकार को बढ़ाने से लेकर करोड़ों देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तक। नियामक बाधाओं, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों, वित्त व संसाधनों की कमी और भौगोलिक विशालता जैसी बाधाओं का सामना करने के बावजूद, भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपने बुनियादी ढांचे के परिदृश्य पर कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं।

विकास को गति देने के अपने प्रयास में भारत सरकार ने कोविड के बाद बुनियादी ढांचे के बजट में लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि की। सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत आवंटन निश्चित ही सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। खासकर परिवहन और रसद क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना बड़े और ठोस लक्ष्य की ओर इंगित करता है। विकास के आईने में सड़कों और राजमार्गों का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद रेलवे और शहरी सार्वजनिक परिवहन का स्थान है। साल 2025 तक 2 लाख किलोमीटर का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करने के लक्ष्य पर देश चल रहा है। इसके लिये तमाम परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जो आने वाल कुछ वर्षों में नए भारत के स्वरूप को दशार्ने वाला होगा।

सिर्फ सड़क परिवहन ही नहीं, सरकार 220 हवाई अड्डों के विस्तार के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। इसके अलावा 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और 2030 तक 23 जलमार्गों का संचालन करना सरकार की महत्वपूर्ण पहलें हैं। इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद भारत निश्चित ही नए लुक में दिखेगा। इन परियोजनाओं को हम नए भारत के निर्माण के लिए ठोस नींव भी कह सकेंगे। इसलिये कि इन परियोजनाओं के बाद विकास रुक नहीं जाएगा। बल्कि विकास की रफ्तार तेज होती रहेगी और नया भारत और ज्यादा नए लुक की तरफ बढ़ता रहेगा। नई पीढ़ी के लिये पुराना

भारत इतिहास, कौतूहल ओर किवदंती बनकर रह जाएगा।

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बेंगलुरू-चेन्नई एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जैसी पहलों के साथ भारत ने आर्थिक विकास के लिए एक नया गलियारा खोलने का निर्णय लिया था। ये सभी परियोजनाएं अंतिम मुकाम के नजदीक हैं। देश में परिवहन सेवाओं के क्षेत्र में ये परियोजनाएं विकास और बदलाव के लिये मील का पत्थर साबित होंगी।

नए भारत के निर्माण के लिये कईयोजनाएं बनाई गई हैं। मल्टीमॉडल कनेक्टीविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य हासिल करने के लिये बना 'प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान', मजबूत राजमार्ग नेटवर्क विकसित करने के लिये 'भारतमाला परियोजना', बंदरगाहों के आधुनिकीकरण व तटीय विकास के लिये 'सागरमाला परियोजना', कमजोर आयवर्ग के लोगों का जीवनस्तर उठाने के लिये 'प्रधानमंत्री आवास योजना', छोटे शहरों में क्षेत्रीय हवाई अड्डों से हवाई संपर्क बढ़ाने के लिये मेट्रो नेटवर्क जैसी परियोजनाएं बदलते भारत की तस्वीर बनाएंगी। इसके अलावा 'स्वच्छ भारत अभियान' के जरिये अपशिष्ट को खाद और सीमेंट में परिवर्तित

सिर्फ सड़क परिवहन ही नहीं, सरकार 220 हवाई अड्डों के विस्तार के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। इसके अलावा 35 मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और 2030 तक 23 जलमार्गों का संचालन करना सरकार की महत्वपूर्ण पहलें हैं। इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद भारत निश्चित ही नए लुक में दिखेगा।

कर निर्माण और रोजगार, दोनों का लक्ष्य कुछ न कुछ हासिल करना बड़ा मकसद है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी और भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययनों के अनुसार, बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए के लिए जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपए की वृद्धि दर्ज की जाती है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है।

भारत सरकार यदि बुनियादी ढांचे में निवेश का सिलसिला जारी रखतीा है, तो न केवल आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलता रहेगा, बल्कि देशवासियों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आर्थिक रूप से जीवंत भारत के लिये अभिनव पहल, रणनीतिक योजनाएं और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता तीनों की जरूरत होगी।

बेशक यह दावा नहीं किया जा सकता कि आने वाले वर्षों में हमारा देश अमेरिका और ब्रिटेन जैसा विकसित बन जाएगा, लेकिन इतना दावा तो किया ही जा सकता है कि ये तमाम परियोजनाएं भारतीयों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने वाली साबित होंगी। हां, अगर जनसंख्या विस्फोट को लेकर भी ठोस व प्रभावी योजनाएं संचालित हों तो अमेरिका जैसा बनना भी मुश्किल काम नहं होगा।

इसके लिये सरकार और देशवासी दोनों को मिलकर काम करना होगा। इसके लिये 'देश सर्वोपरि और धर्म, सम्प्रदाय व जाति बाद में' की सोच बनानी होगी। कहना गलत नहीं होगा कि निर्माण व आर्थिक योजनाओं से ही हम नए और विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकेंगे, हमें सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनना होगा। हमें अपनी सोच भी बड़ी करनी पड़ेगी।

देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं नितिन गडकरी

मोदी और शाह के सहयोग एवं प्रोत्साहन से विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं गडकरी

ललित कुमार

भारत इस समय तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस समय चार से अधिक ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गयी है। भारतीय इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी निभा रहे हैं। यह तो सभी को ज्ञात है कि किसी देश की इकोनॉमी उस देश के कारोबार पर आश्रित होती है। कारोबार उस देश के आवागमन के साधनों पर आश्रित रहता है। यदि आवागमन के साधन सुलभ हों तो वहां का कारोबार तेजी से आगे बढ़ता है। इसी फार्मूले को समझते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के आवागमन के संसाधनों का जाल बिछाने का संकल्प लिया, जो आज पूरी तरह से सफल हो रहा है। नितिन गडकरी के इस हुनर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय परखा था जब वो महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री हुआ करते थे और उस समय उन्होंने अपने कार्यकाल में मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे मार्ग बनवाया था। उस समय ही श्री वाजपेयी ने उन्हें केन्द्र की मार्ग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। श्री गडकरी के सुझाव पर ही देश की लोकप्रिय सड़क योजना की बुनियाद रखी गयी थी।2014 में जैसे ही भाजपा के नेतृत्व में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो सबसे पहले उनकी नजर नितिन गडकरी पर पड़ी और उन्होंने उन्हें सड़क परिवहन, राजमार्ग के साथ जल मार्ग की भी जिम्मेदारी सौंपी। श्री गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरते ही अपने विभाग की गाड़ी को एक्सप्रेस की तरह दौड़ा दिया। दशकों से डिब्बों में बंद पड़ी परियोजनाओं को सरपट तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया और देश को आर्थिक तरक्की की राह पर ला दिया। श्री गडकरी को पीएम श्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही अमित शाह का भी पूर्ण सहयोग मिला, जो इस सरकार का सामूहिक नेतृत्व कर रहे थे। अपने पांच साल के पहले कार्यकाल में देश में इतने हाईवे बनवाये कि श्री गडकरी को देश का हाईवे मैन कहा जाने लगा। 2019 के दूसरे कार्यकाल में भी मोदी-शाह ने श्री गडकरी पर पुन: विश्वास जताया और उन्हें उनके ही विभाग सौंप दिये। उसका कारण यह माना जा रहा था कि पहले कार्यकाल में उन्होंने इतने कार्य कराये थे कि देश के 67 साल के इतिहास में किसी भी मंत्री ने इतने काम नहीं कराये थे। इसके बाद तो श्री गडकरी ने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोज नये-नये प्रोजेक्ट से देश को विश्व के पहले पायदान पर पहुंचाने में लगे हुए हैं और जल्द ही मोदी-शाह के सहयोग से इस स्थान पर कर भारत यूएसए और चीन को पछाड़ देगा।

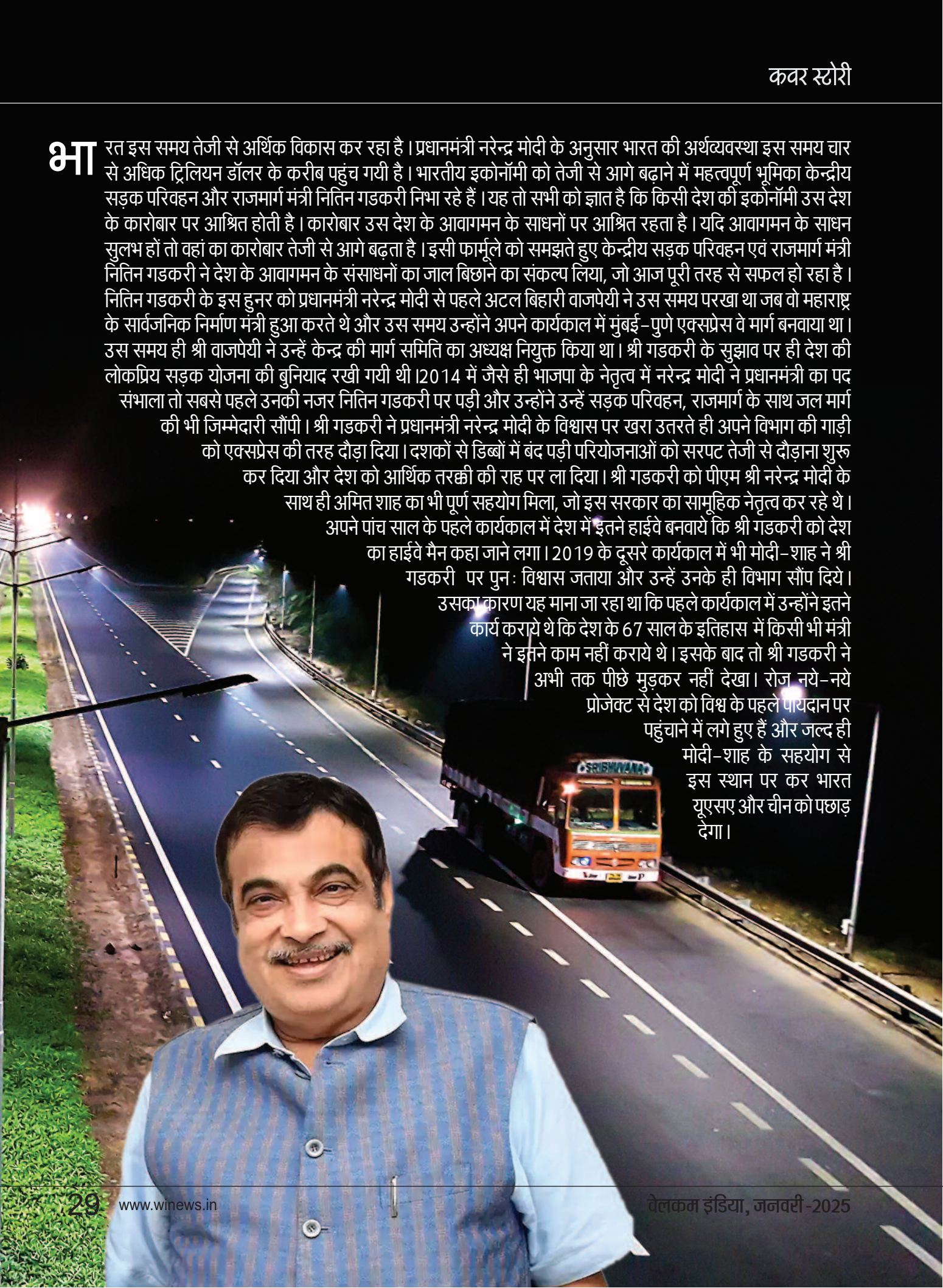

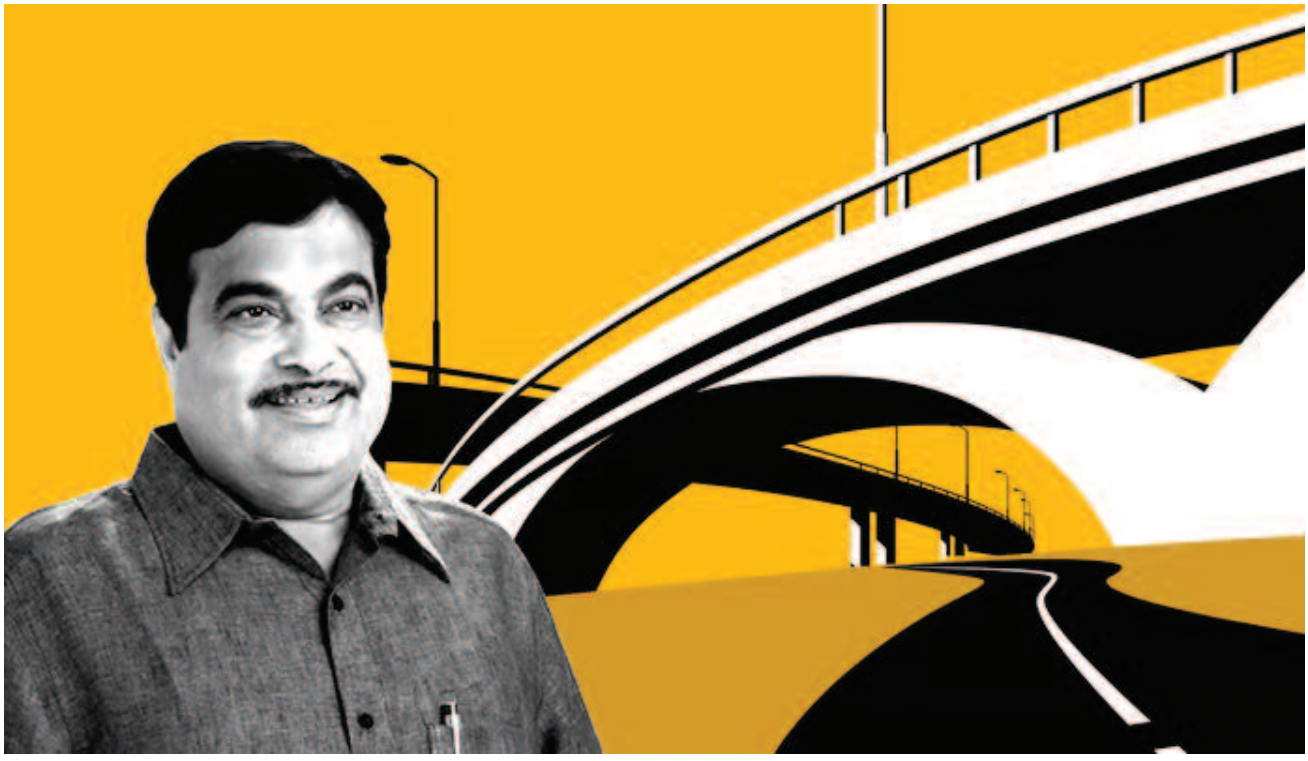

जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा ही करके मानते हैं गडकरी

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लोकप्रिय रूप से 'भारत के हाईवे मैन' के रूप में जाना जाता है। वो जो भी काम हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से ताल्लुक रखने वाले 67 वर्षीय नेता सबसे लंबे समय तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पिछली दो सरकारों में उन्होंने यह मंत्रालय संभाल रखा है। श्री गडकरी को पिछले 10 वर्षों में देश में 90,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों और 30,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। उनका कहना है कि कि वह जमीन से जुड़े लोगों की यथासंभव छोटी से छोटी मदद करना चाहते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते रहना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकटता से जुड़े पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने नागपुर लोकसभा सीट से लगातार तीन बार जीत हासिल की है, जहां आरएसएस का मुख्यालय है।

गडकरी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश तब हुआ जब उन्हें 2009 में भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2014 में जब गडकरी ने नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और केंद्र में मंत्री बने, तब से उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे कई विभागों को संभाला है। मंत्री बनने के बाद से गडकरी ने राजनीतिक रूप से खुद को कम महत्वपूर्ण रखा है और अपने मंत्रालयों पर ध्यान केंद्रित किया है।

उन्होंने 1989 से 2014 तक नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 1995 में पहली बार राज्य मंत्री बने और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) का प्रभार संभाला। इस अवधि के दौरान उन्होंने राज्य में बारहमासी सड़कों के निर्माण और विदर्भ क्षेत्र के मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए काम किया। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और महाराष्ट्र की राजधानी में 54 फ्लाईओवर का निर्माण राज्य मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। बांद्रा-वर्ली सी लिंक की परिकल्पना भी गडकरी के लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल के दौरान की गई थी।

नितिन गडकरी के लिए राजनीतिक पेशा नहीं मिशन

मोदी सरकार में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी लाइन से हटकर और आम जनता के बीच अपने व्यापक काम के लिए सराहा जाता है। एक व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी संगति से होता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ लंबे समय से जुड़े नितिन गडकरी में प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन, नेतृत्व, नवाचार और रचनात्मकता जैसे गुण हैं, साथ ही राष्ट्र-प्रथम दृष्टिकोण भी है। सड़क और जलमार्गों द्वारा परिवहन क्षेत्र का परिवर्तन आश्चर्यजनक है। उनके काम का सबसे अच्छा पहलू यह है कि वे दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न नवीन अवधारणाओं का अध्ययन करने और पूरे देश में सर्वोत्तम लागू प्रथाओं के साथ उन्हें लागू करने का प्रयास करने में विश्वास करते हैं। परियोजना पूर्ण होने की गति में तेजी से वृद्धि निस्संदेह उनकी व्यक्तिगत भागीदारी और परियोजनाओं के गहन अध्ययन के साथ-साथ परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को हल करने और नौकरशाही को कुशलतापूर्वक काम करने के उनके प्रयासों के कारण है, जो कई मामलों में एक कठिन काम है। किसी भी देश का औद्योगिक विकास, और इस प्रकार आर्थिक विकास, केवल तभी संभव है जब उसका परिवहन क्षेत्र जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह से विकसित हो, और वह इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और कार्य में आगे बढ़ रहे हैं।

फ्लाईओवर मैन के नाम से पहले ही लोकप्रिय थे

महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में गडकरी की भूमिका मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने में महत्वपूर्ण थी। महाराष्ट्र सरकार ने 1990 में नए एक्सप्रेसवे के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराया, जिसे टोल के आधार पर संचालित किया जाना था, लेकिन जब तक गडकरी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, तब तक इस परियोजना के निर्माण में तेजी नहीं आई। राज्य मंत्री के रूप में गडकरी की अन्य प्रमुख उपलब्धि मुंबई में 55 फ्लाईओवर का निर्माण था, जिसने उस समय शहर की यातायात समस्याओं को काफी कम कर दिया।राज्य में पहली बार इतने अधिक फ्लाई ओवर बनवाने वाले व्यक्ति श्री गडकरी फ्लाई ओवर मैन के नाम से लोकप्रिय हो गये।

पहली बार बने केन्द्रीय मंत्री की कामयाबी के चंद नमूने

मई 2014 में गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के साथ-साथ शिपिंग मंत्री भी नियुक्त किया गया। उन्हें विरासत में मिली रुकी हुई परियोजनाओं में से 1 ट्रिलियन (13 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की परियोजनाओं को समाप्त कर दिया गया और 350 बिलियन (4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की अन्य परियोजनाओं को फिर से बोली के लिए रखा गया। उन्होंने अपने पहले वर्ष में देश की सड़क निर्माण दर को 2 किमी/दिन से बढ़ाकर 16.5 किमी/दिन, दूसरे वर्ष में 21 किमी/दिन, 2018 के अंत में 30 किमी/दिन और आज 37 किमी/दिन कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए कुल प्रोजेक्टों में से एक प्रतिशत, जो कुल 2 ट्रिलियन (27 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था, पेड़ों और सौंदर्यीकरण के लिए अलग रखा।

- पिछले 7 वर्षों में, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किमी (अप्रैल 2014 तक 67 वर्ष) से 50% बढ़कर 1,37,625 किमी (20 मार्च 2021 तक) हो गई है।
- कुल बजटीय परिव्यय में 5.5 गुना वृद्धि हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2015 में 33,414 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में 1,83,101 करोड़ रुपये हो गया है।
- कोविड-19 संबंधित प्रभाव के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में स्वीकृत राशि में 126% की वृद्धि हुई है। किलोमीटर में स्वीकृत लंबाई भी वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 9% बढ़ी है।
- वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान औसत वार्षिक निर्माण (औसत वार्षिक निर्माण लंबाई) वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2014 की तुलना में 83% बढ़ गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 के अंत में चल रहे परियोजना कार्यों की संचयी लागत में 54% की वृद्धि हुई है (31 मार्च तक)
- नितिन गडकरी की दक्षता तीन साल के रिकॉर्ड समय में दिल्ली के चारों ओर पूर्वी और पश्चिमी परिधीय राजमार्गों के निर्माण में देखी जा सकती है। इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए इसके निर्माण का आदेश दिया था, 2014 तक कुछ नहीं हुआ। नितिन गडकरी के इस मंत्रालय को संभालने के बाद, फाइलें बहुत तेजी से आगे बढ़ीं और दोनों राजमार्ग अब पूरे हो गए हैं।
- भारत माला योजना के तहत 65,000

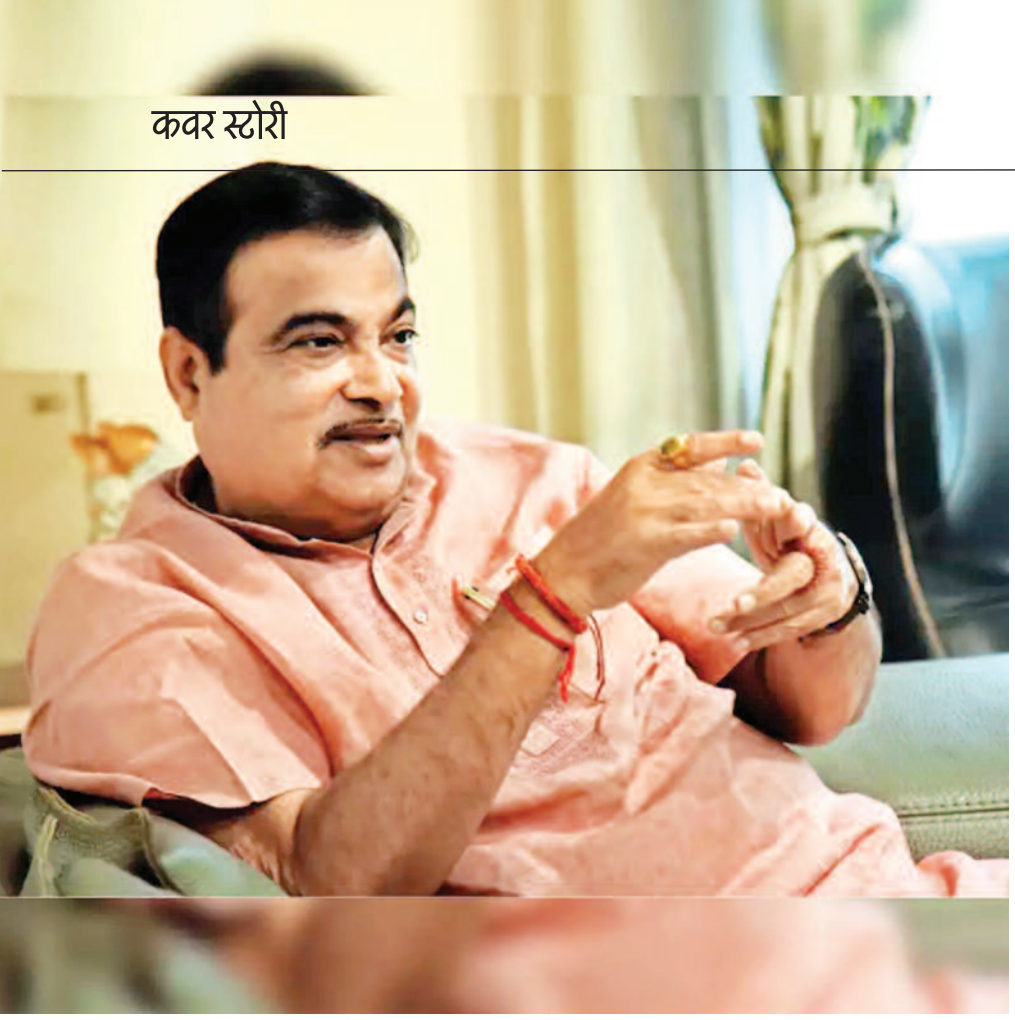

किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरे देश में फैले नए और मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विशाल नेटवर्क को संदर्भित करता है। भारतमाला परियोजना, भारत में दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण परियोजना है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आर्थिक गलियारों, सीमावर्ती क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करना है। आज तक लगभग 40,000 किलोमीटर नई सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने पिछले चार वर्षों में 700 से अधिक चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 40 प्रतिशत से अधिक को पूरा किया, जो सरकार की दक्षता को दर्शाता है, जो अक्सर लालफीताशाही संस्कृति से प्रभावित होती है। इस परियोजना से पूरे भारत में बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि के परिणामस्वरूप लगभग 22 मिलियन नौकरियाँ और 100 मिलियन मानव दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

- इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, पूर्वोत्तर राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया और पिछले प्रशासनों द्वारा शुरू की गई लेकिन पूरी नहीं हो सकी कई परियोजनाओं में तेजी लाई गई। असम में ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल-रोड पुल, जो पिछले दो दशकों से निर्माणाधीन है, इनमें सबसे अधिक दर्शनीय है। मोदी सरकार से पहले ब्रह्मपुत्र पर तीन पुल थे और पिछले पांच वर्षों में तीन और पुल पूरे हो गए हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं, जो इस सरकार की काम करने की गति को दर्शाता है।
- **शिपिंग** – भारतमाला के समान, शिपिंग मंत्रालय ने सागरमाला बंदरगाह और तटीय क्षेत्र विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। सागरमाला कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास, बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने, बंदरगाह से जुड़े औद्योगीकरण और तटीय सामुदायिक विकास के क्षेत्रों में, 2015-2035 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 574 से अधिक परियोजनाओं (लागतः 6.01 लाख करोड़ रुपये) की पहचान की गई है। 30 सितंबर 2019 तक कुल 121 परियोजनाएं (लागतः 30,228 करोड़ रुपये) पूरी हो चुकी हैं और 201 परियोजनाएं (लागतः 309,048 करोड़ रुपये) क्रियान्वयन में हैं। कुल लागत में शामिल हैं;
- **बंदरगाह आधुनिकीकरण** – 245 परियोजनाएं (21 बिलियन अमेरिकी डॉलर);
- **कनेक्टिविटी वृद्धि** – 210 परियोजनाएं (36 बिलियन अमेरिकी डॉलर);
- **बंदरगाह से जुड़ा औद्योगिकीकरण** – 57 परियोजनाएं (68 बिलियन अमेरिकी डॉलर); और, ड्र तटीय सामुदायिक विकास - 65 परियोजनाएं (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर)। क्योंकि हममें से अधिकांश का महासागरों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम इन परियोजनाओं की भयावहता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लोग, विशेष रूप से समुद्री परिवहन से जुड़े लोग, समझ जाएंगे
- भारतीय अंतदेर्शीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), जो 1986 से अस्तित्व में था, मोदी सरकार के दौरान अस्तित्व में आया, जिसके साथ अंतदेर्शीय जलमार्ग विकास पर वास्तविक कार्य शुरू हुआ। पहला कंटेनर जहाज हल्दिया, पश्चिम बंगाल से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ। भारत में इस पर कभी विचार नहीं किया गया।
- **क्रूज** – इस तथ्य के बावजूद कि क्रूज शिपिंग नीति की घोषणा 2008 में की गई थी, क्रूज पर्यटन के विकास में कोई प्रगति नहीं हुई है। एनडीए सरकार ने कार्रवाई की और पाँच प्रमुख बंदरगाहों में विशेष क्रूज टर्मिनल बनाए: मुंबई, मोरमुगाओ (गोवा), मैंगलोर, कोचीन और चेन्नई। सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत में अब मुंबई और गोवा के बीच अपनी पहली घरेलू क्रूज सेवा है।
- वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा झ यह कोई रहस्य नहीं है कि नितिन गडकरी वैकल्पिक ईंधन के प्रशंसक हैं। सड़कों और ऑटोमोबाइल के बारे में उनका ज्ञान उद्योग में उनके पूरे जीवन को शर्मसार कर देगा। वे अक्सर 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' का जिक्र करते हैं। भारत के बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद करने के लिए, वे इथेनॉल, मेथनॉल और अन्य जैसे वैकल्पिक ईंधन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें घरेलू स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से बनाया जा सकता है और इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यह सूची बहुत लंबी है। कोरोना के सबसे बुरे दौर के बाद भी परिवहन क्षेत्र में आए बड़े बदलाव से अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों को भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आने वाले समय में जब परियोजनाएं पूरी तरह से चालू हो जाएंगी, तो और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

खुशखबरी: दो दर्जन से अधिक एक्सप्रेस-वे बनने को हैं तैयार

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यकाल में बनी अनगिनत परियाजनाओं ने देश को शिखर पर ले जाने का काम किया है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे से अपना सफर शुरू करने वाले श्री गडकरी ने अब तक सैकड़ों परियोजनाओं को पूर्ण करके देश को आर्थिक प्रगति के शिखर पर पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका यह सफर अभी भी लगातार उसी रफ्तार से चल रहा है। आने वाले समय में दो दर्जन से अधिक परियोजनाएं देश का कायाकल्प करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार नई सड़क परियोजनाओं तथा एक्सपेंशन के साथ भारत की परिवहन अवसंरचना में लगातार इजाफा कर रही है। वर्तमान में, आवागमन को आसान बनाने के लिए कई राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। भारत में आने वाले प्रमुख एक्सप्रेसवे के बारे में जानने के लिए आगे पढ़ें।

1. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
2. द्वारका एक्सप्रेसवे
3. मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे
4. गंगा एक्सप्रेसवे
5. दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे
6. अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे
7. बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे
8. रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे
9. नर्मदा एक्सप्रेसवे
10. लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे
11. गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे
12. अमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे
13. फरीदाबाद- जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे
14. रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे
15. आगरा-बरेली एक्सप्रेसवे
16. अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेसवे
17. जेवर एयरपोर्ट-न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे
18. गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे
19. कांगड़ा शिमला हाईवे
20. हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे

भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। क्रमशः, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय सड़क नेटवर्क का विकास तेजी से हो रहा है, और जल्द ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पछाड़ कर पहले स्थान पर आ सकता है।

भारत का सड़क नेटवर्क हर बड़े शहर को अपनी राष्ट्रीय सड़कों, राजमार्गों, ओवरपास व एक्सप्रेसवे से छोटे से छोटे शहर से जोड़ता है। सरकार नए बनने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के आसपास रडर बूथ, स्पीड मापने की व्यवस्था, पुलिस व एम्बुलेंस सेवाओं जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सड़क के जरिए यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए भारत जल्द ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। वीडी और बिग डेटा जैसी तकनीक का इस्तेमाल ड्राइविंग को सुरक्षित और अधिक कुशल बना देगा। आज भारत हर चीज को वर्ल्ड क्लास बनाने पर फोकस कर रहा है।

1. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

इस एक्सप्रेस वे को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यह फेज 1 का एक हिस्सा है जिसकी लंबाई लगभग 1350 किमी है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसमें हर 100 किमी पर दुर्घटना के पीड़ितों के लिए ट्रॉमा सेंटर होंगे और पूरे मार्ग पर 93 जगह ठहरने की व्यवस्था होगी। भारतीय वन्यजीवों पर प्रभाव न पड़े इसके लिए इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक की ध्वनि का उपयोग हॉर्न और सायरन के रूप में किया जाएगा। साथ ही यह पहला हाईवे है जिसमें दिल्ली से मुंबई जाने वाले रास्ते पर 12 हेलीपैड होंगे। दौसा में चार, सवाई माधोपुर में छह और कोटा में दो बनाएं जाएंगे; इन हेलीपैड का उपयोग चिकित्सा आपात स्थिति, रक्षा संबंधी गतिविधियों और अन्य कामों के लिए किया जाएगा।

एक्सप्रेसवे चालू होने पर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 12.5 घंटे में तय हो जाएगी। अब पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अक्टूबर 2025 तक होगा है।

2. द्वारका एक्सप्रेसवे

पहले आठ लेन को भारत में शहरी एक्सप्रेसवे को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और यह दिल्ली में महिपालपुर को हरियाणा के खेरकी दौला टोल प्लाजा से जोड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे से एनएच-8 पर ट्रैफिक कम होगा और प्रतिदिन 3 लाख यात्रियों इसपर यात्रा करेंगे। यह 29.10 किमी लंबी प्रोजेक्ट है, 18.9 किमी गुड़गांव में और 10.1 किमी दिल्ली में है। एक्सप्रेसवे पर समय, देरी, गति, सड़क दुर्घटनाओं, रुट में बदलाव और वर्क जोन जैसी जानकारी के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्सप्रेसवे के साथ एक मेट्रो मार्ग का प्रस्ताव दिया है, जिसकी मंजूरी अभी मिलनी बाकी है।

3. मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे

समृद्धि महामार्ग या मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किमी का है, जो 390 गांवों और दस जिलों को जोड़ेगा। यह जिन प्रमुख शहरों को जोड़ेगा उनमें नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, शिर्डी, भिवंडी और वर्धा शामिल हैं। एक्सप्रेसवे से मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा का समय आठ घंटे तक कम हो जाएगा है। वर्तमान में, नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14-15 घंटे लगते हैं। यह ऐसा राजमार्ग है जिसपर 150 किमी/घंटा की गति सीमा से यात्रा की जा सकेगी। एक्सप्रेसवे को 2021 में शुरू होना था; हालाँकि, कोरोना वायरस महामारी के कारण, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम इसमें देरी कर रहा है।

4. गंगा एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे छह लेन की राजमार्ग प्रोजेक्ट है जो मेरठ में एनएच-334 को एनएच- 2 प्रयागराज बाईपास से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर छह घंटे कर देगा। यह मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होती है और प्रयागराज के जूदापुर दंडू गांव में समाप्त होगा। इसमें प्रयागराज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, चंदौसी, तिलहर, बांगरमऊ, रायबरेली, हापुड़ और सियाना जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। बन जाने के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा।

5. दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से होकर जम्मू-कश्मीर में कटरा तक जाता है। कवर किए जाने वाले प्रमुख शहर नोकदार, अमृतसर और गुरदासपुर हैं। साथ ही, यह चार लेन का एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है क्योंकि यह हिंदुओं और सिखों के दो पवित्र शहरों - माता वैष्णो देवी मंदिर और स्वर्ण मंदिर को जोड़ता है। चिकित्सा आपात स्थिति के लिए ट्रॉमा सेंटर, कॉल पर एम्बुलेंस, अग्निशमन की व्यवस्था, मनोरंजक सुविधाएं, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्टॉप और रेस्तरां जैसी सुविधाएं एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हैं।

6. अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे

अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे की घोषणा 2010 में की गई थी, लेकिन इसे 2019 में हरी झंडी मिल गई। यह चार लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे सरखेज में सरदार पटेल रिंग रोड से नवगाम में धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच बना है। यह धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र को भी जोड़ता है। इस 109 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के जमीन खरीदने का काम 2020 में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूरा किया गया था।

7. बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे

यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख आगामी एक्सप्रेसवे है। यह चार-लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे दक्षिण भारत के दो राज्यों के दो राजधानी शहरों चेन्नई को बैंगलोर से जोड़ता है। यह स्ट्रेच कर्नाटक में होसकोटे और बांगरपेट, आंध्र प्रदेश में पलमनेर और चित्तूर और तमिलनाडु में श्रीपेरंबदूर के बीच 260 किमी तक है। इससे दूरी 50 किमी कम हो जाएगी और

वाहन 120 किमी/घंटा की गति से चल सकते हैं।

8. रायपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे

रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर का हिस्सा, यह छह-लेन एक्सप्रेसवे 464 किमी का है। यह मध्य और पूर्व-मध्य भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में रेड कॉरिडोर से होकर गुजरता है। इससे यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर 7 घंटे हो जाएगा और दूरी 590 किमी से घटाकर 464 किमी हो जाएगी।

9. नर्मदा एक्सप्रेसवे

नर्मदा एक्सप्रेसवे 8-लेन का हाईवे प्रोजेक्ट है जो लोकप्रिय नर्मदा नदी के किनारे बनेगा और मध्य प्रदेश राज्य में पूर्व-पश्चिम मार्ग को जोड़ेगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पूर्वी मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के जबलपुर, अलीराजपुर और डिंडोरी से जोड़ेगा। यह मोटर मार्ग गुजरात राज्य और छत्तीसगढ़ को जोड़ेगा। अहमदाबाद और अलीराजपुर को जोड़ने के लिए राजमार्ग का एक नया फेज बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले नर्मदा एक्सप्रेसवे की कुल लागत 31,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

10. लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे

भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक बहुप्रतीक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यह 62 किमी लंबा, 6-लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है जो एनएच-27 के समानांतर बना है और लखनऊ तथा कानपुर को जोड़ेगा। भारत के इस एक्सप्रेसवे पर दो एलिवेटेड हिस्से, तीन बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और छह फ्लाईओवर बनेंगे। इसकी आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी और दिसंबर 2020 में इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 6 अधिसूचित किया गया था। उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे से यात्रा के समय को कम करके, कनेक्टिविटी में सुधार और व्यापार को बढ़ाकर क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह यात्रियों को एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा। यह प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड-अपग्रेड दोनों है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए यूपी सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

11. गोरखपुर शामली एक्सप्रेस वे

गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और 37 तहसीलों से गुजरते हुए 700 किमी का होगा। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कवर करेगा। दोनों शहरों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगी, क्योंकि अभी गोरखपुर से आते वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली जाना पड़ता है। एक्सप्रेसवे अंतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराईच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहाँपुर, हरदोई, बदायूँ, रामपुर, मोरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली से होकर गुजरेगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

12. अमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे

अमास-दरभंगा एक्सप्रेसवे, जिसे गया दरभंगा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है, गया को दरभंगा से जोड़ने वाला 230 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नए साल 2024 में किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सात जिलों - औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा से होकर गुजरेगा।

एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एसए इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पहले ही तैयार की जा चुकी है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी 2020 में शुरू हो गई है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं :- एक्सप्रेसवे का प्रारंभिक बिंदु गया जिले का अमास गांव है, और अंतिम बिंदु दरभंगा जिले का बेला नवादा गांव है। परियोजना की अनुमानित लागत 5000 करोड़ रुपये है। चार एक्सप्रेसवे लेन प्रस्तावित हैं लेकिन बाद में इन्हें बढ़ाकर छह किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है और बोली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चार पैकेजों में किया जाएगा।

13. फरीदाबाद- जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे

फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जून 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 31.4 किलोमीटर लंबा होगा, जो फरीदाबाद के सेक्टर 65 से शुरू होकर जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खत्म होगा। फरीदाबाद-जेवर एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई लिंक रोड से जुड़ेगा। 31.4 किलोमीटर में से सात किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और बाकी 24 किलोमीटर हरियाणा के फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में 12 गांवों से होकर गुजरेगा। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच की दूरी 90 किमी है और एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद यह दूरी घटकर 34 किमी रह जाएगी।

यात्रा का समय एक घंटे से घटकर 15-30 मिनट रह जाएगा। जेवर एयरपोर्ट हाईवे को केजीपी एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा और यूपी सीमा के पास मोहना-बागपुर-फलैदा रोड पर प्रवेश/निकास रैंप का निर्माण किया जा रहा है।

14. रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे

भारतमाला परियोजना के तहत बनने वाला एक अन्य एक्सप्रेसवे रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे देवघर और जामताड़ा से गुजरेगा और पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह के पास समाप्त होगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे से देवघर और पटना, कोलकाता और हल्दिया जैसे अन्य शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र तीन घंटे रह जाएगा। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में से देवघर में खंड की लंबाई लगभग 65 किलोमीटर होगी। साथ ही, जामताड़ा में खंड की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर होगी। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे पूर्वी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर और बेगूसराय जैसे शहरों से गुजरेगा, सूर्यगढ़ा से मलयपुर, चिरयंडी, बांका के कटोरिया, देवघर के मोहनपुर तक एक नए पुल के माध्यम से गंगा नदी को पार करेगा। यह नागपुर, घोरमारा, सोनारायठाढ़ी और जामताड़ा के पालोजोरी से भी गुजरेगा। जामताड़ा के बाद यह कुंडहित, बोलपुर, आरामबाग, राजहट्टी, पूर्वी मिदनापुर और अंत में हल्दिया बंदरगाह से गुजरेगा।

15. आगरा-बरेली एक्सप्रेसवे

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यात्रा समय को कम करने और यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आगरा और बरेली के बीच एक एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रहा है। एक्सप्रेसवे मार्ग मथुरा से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 228 किलोमीटर होगी और आगरा बरेली एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमानित लागत करीब 4,000 करोड़ रुपये है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। आगरा-बरेली एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर दो शहरों के बीच यात्रा का समय चार घंटे तक कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे परियोजना में विभिन्न फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है जो मार्ग पर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करते हुए यातायात की भीड़भाड़ की समस्या को कम करने में मदद करेगा।

16. अलीगढ़-पलवल एक्सप्रेसवे

अलीगढ़ और पलवल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सरकार एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाएगी। यह एक्सप्रेसवे कुल 32 किलोमीटर का होगा और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ पलवल एक्सप्रेसवे टप्पल (यमुना एक्सप्रेसवे) से शुरू होकर पलवल (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे) पर समाप्त होगा। इससे इन शहरों के बीच यात्रा का समय एक घंटे तक कम हो जाएगा। इससे आगरा, मथुरा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, पलवल और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी।

17. जेवर एयरपोर्ट-न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे

एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट - न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे है, जिसे नोएडा मास्टर प्लान 2041 के तहत मंजूरी दी गई है। यह एक्सप्रेसवे दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र का विस्तार करने और उत्तर प्रदेश के जिलों से कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद करेगा। बन जाने के बाद, यह एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई सिर्फ.16 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नए नोएडा से जोड़ेगा, जिससे नए बनने वाले एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट को रुंधी से चोला तक रेलवे लाइन से जोड़ेगा और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। 4 से 6 लाइनों वाले जेवर एयरपोर्ट-न्यू नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। दो कनेक्टिंग लोकेशन के अलावा, पड़ोसी जिलों से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

18. गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश में कई अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के साथ, गाजियाबाद और कानपुर के बीच एक और एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है, ताकि दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके तथा यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, जिसमें 4 लेन होंगे, जिन्हें भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। प्राधिकरण ने भविष्य में नोएडा स्थित जेवर हवाई अड्डे से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ने की भी बात कही है। एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर गाजियाबाद और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर साढ़े पांच घंटे रह जाएगा। वर्तमान में इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 8 घंटे है।

19. कांगड़ा-शिमला हाईवे

2023 में एनएचअथॉरिटी ने शिमला से कांगड़ा और रानीताल तक हाईवे का निर्माण शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को पांच अलग-अलग पैकेज में बांटा गया है। हाईवे के निर्माण में चार हाई-राइज पुल और नौ सुरंगों का निर्माण शामिल है। निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है, क्योंकि अबतक 90% काम हो चुका है। इसके निर्माण से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय छह घंटे से घटकर चार घंटे रह जाएगा। साथ ही, शिमला कांगड़ा हाईवे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रुट की लंबाई 45 किलोमीटर कम हो जाएगी। शिमला कांगड़ा हाईवे का नए अलाइनमेंट में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग 88 का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में इस हाईवे को एनएच-103 के नाम से जाना जाता है। यह हाईवे रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरता है। इनमें से कुछ शहरों में दरलाघाट, बिलासपुर, हमीरपुर और ज्वालामुखी शामिल हैं।

20. हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे

इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य तेलंगाना और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और राज्य के विभिन्न शहरों तक भी निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। चालू होने के बाद, एक्सप्रेसवे से हैदराबाद और इंदौर के बीच यात्रा का समय आठ घंटे कम होने की उम्मीद है। वर्तमान में, इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 18 घंटे है। हैदराबाद-इंदौर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाईः 713 किमी।

भारत में बनने वाले अन्य एक्सप्रेसवे की सूची इस प्रकार है:-

बैंगलोर मंगलुरु एक्सप्रेसवे

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की योजना हसन से गुजरते हुए बैंगलोर और मंगलुरु के बीच एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की है। एक्सप्रेसवे चालू हो जाने के बाद, दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 7 से 8 घंटे कम हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कर्नाटक लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जुलाई 2024 में, प्राधिकरण ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए बोलियाँ आमंत्रित कीं। नवंबर तक, प्राधिकरण को नौ कंपनियों से बोलियाँ मिलीं; जनवरी तक, मंत्रालय निविदा सौंपेगा, और उनके पास इसे पूरा करने के लिए 540 दिन होंगे।

कोंकण एक्सप्रेसवे

महाराष्ट्र सरकार गोवा और मुंबई के बीच 376 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रही है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। मुंबई से गोवा पहुंचने में केवल छह घंटे लगेंगे, वर्तमान में इसमें लगभग 12-13 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे सिंधुदुर्ग से होते हुए रायगढ़ और रत्नागिरी से गुजरते हुए नवी मुंबई के पनवेल तक जाएगा।

मुंबई-पुणे-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से पिंपरी चिंचवाड़ में ट्रैफिक में कमी आएगी। एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा 55,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। मुंबई-पुणे-बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पिंपरी चिंचवाड़ से होते हुए रिंग रोड से होकर गुजरेगा। इस परियोजना के तहत पुणे में सोलापुर-यावत और नरहे-रावेत सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। सोलापुर-यावत और नरहे-रावेत सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 7000 करोड़ रुपये की लागत से एक एलिवेटेड रोड का निर्माण भी किया जाएगा।

खड़गपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे

ओडिशा सरकार ने खड़गपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की है, जो ओडिशा से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से वाहनों का आवागमन सुगम होने और कनेक्टिंग रुट्स पर ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। यह एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में भी काम करेगा, जो वाहनों के लिए हाई-स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्रदान करेगा।

केंद्र के गति शक्ति ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और ओडिशा की सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाएगा। वर्तमान में, दस से अधिक फर्मों ने एक्सप्रेसवे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी बोलियाँ प्रस्तुत की हैं। बोलियों का तकनीकी आकलन पूरा होने के बाद, 2026 के अंत तक रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा। अनुमोदन प्रक्रिया, आवश्यक मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के बाद, एक्सप्रेसवे का निर्माण 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है।

इनमें से अधिकांश एक्सप्रेसवे से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का वर्तमान रिकॉर्ड टूटा है। इन एक्सप्रेसवे से भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में पहले या दूसरे स्थान पर आ सकता है। साथ ही, ये प्रोजेक्ट्स देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। ये सभी एक्सप्रेसवे दूरी और यात्रा के समय को बेहद कम कर देंगे। इससे यात्रा सुरक्षित और आसान होगी!

योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने मिलकर उत्तर प्रदेश की काया ही पलट दी

पूरे भारत में अपनी कुशल राजनीति से निचले तबके के दुखों को हरने वाले नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में भी अपने हुनर का जादू बिखरा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से अभूतपूर्व विकास कार्य कराये। प्रदेश में हाईवे का ऐसा जाल बिछाया कि राज्य का कोई भी गांव अब सड़क यातायात से अछूता नहीं रह गया।

यही नहीं गडकरी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आश्चर्यजनक रूप से ऐसे-ऐसे कार्य किये कि जनता सुखी एवं सम्पन्न तो हुई ही साथ ही सम्पन्न भी हो गयी। राज्य में हुए हाइवे निर्माण से शहरों की दूरी कम हो गयी। इससे आम आदमी का समय व पैसा दोनो बचा। इसका सबसे अधिक लाभ व्यापारी वर्ग को हुआ। व्यापारियों का कारोबार बढ़ा। उनकी पहुंच आम गांवों तक हो गयी। इससे इन गांवों में रहने वालों को अपने ही स्थान पर समुचित रेट पर उचित सामान मिलने लगा। व्यापारियों का कारोबार बढ़ने से देश का आर्थिक स्तर भी सुधरने लगा, जो अभी भी जारी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केन्द्र का साथ मिलने पर पूरे प्रदेश में सड़कों का ऐसा जाल

सचिन तोमर

बिछाया कि राज्य तेजी से तरक्की की राह पर निकल गया। यही नहीं राज्य का आर्थिक स्तर भी काफी ऊँचा उठ गया। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का साथ दिया, उसका पूरा-पूरा लाभ उन्हें मिला। उत्तर प्रदेश जिसे कभी रुग्ण प्रदेश की संज्ञा दी जाती है वो आज देश के प्रमुख आर्थिक राज्यों को कड़ी टक्कर दे रहा हैं। श्री गडकरी और योगी आदित्यनाथ का आपसी सहयोग से कार्य चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के नंबर वन संपन्न राज्य जायेगा। इस राज्य पर धन-धान्य की वर्षा करने वाले राज्य के एक्सप्रेसवे हैं, इनमें से कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे का विवरण इस प्रकार है:-

उत्तर प्रदेश सरकार सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने यूपी में 16 एक्सप्रेसवे शुरू किए हैं, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो गया है।

1. **यमुना एक्सप्रेसवे :** उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे
2. **नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे :** यूपी का एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे
3. **आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे :** यूपी का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
4. **दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे :** यूपी का एक लोकप्रिय एक्सप्रेसवे
5. **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे :** यूपी में बना एक नया एक्सप्रेसवे
6. **बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे :** यूपी का सबसे कम समय में बना एक्सप्रेसवे
7. **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे :** गोरखपुर के आर्थिक विकास में सुधार
8. **गंगा एक्सप्रेसवे :** यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे
9. **लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे :** यूपी का एक खास एक्सप्रेसवे
10. **गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे :** यूपी का आगामी एक्सप्रेसवे
11. **गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे :** पश्चिम

बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार

12. **दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे :** यूपी में आगामी एक्सप्रेसवे
13. **गाजीपुर - बलिया - मांझी घाट एक्सप्रेसवे : यूपी का आगामी एक्सप्रेसवे**
14. **गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे :** यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे
15. **यूपी में एक अन्य एक्सप्रेसवे - आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे**
16. **चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे**

यूपी में जल्द ही बनकर तैयार होने वाले ये एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक विकास को गति देंगे। अवसंरचना के विकास से यहां के रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगी। ये सभी एक्सप्रेसवे भारत में भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे पहले से ही बन चुके हैं, जबकि कई और एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं।

1. यमुना एक्सप्रेसवे

यूपी का यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यह कई पुलों और सात इंटरचेंजों वाला यह एक एक्सेस-कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद अब दिल्ली से आगरा का सफर दो से ढाई घंटे का हो गया है। इस एक्सप्रेस-वे का डिजाइन वाहनों की सुरक्षा तथा निगरानी से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था।

एक्सप्रेसवे के हर 25 किमी पर एक हाईवे पेट्रोलिंग है। एक्सप्रेसवे को तीन चरणों में बनाया गया है। इसका पहला चरण ग्रेटर नोएडा से ताज इंटरनेशनल एविएशन हब तक है, यानी जेवर गांव के आसपास। दूसरा चरण ताज इंटरनेशनल एविएशन हब से एविएशन हब के बीच में है। प्रोजेक्ट का तीसरा चरण एविएशन हब से आगरा तक है। यमुना एक्सप्रेसवे पर पांच टोल प्लाजा हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में रियल एस्टेट को गति मिली है। इसने आस-पास के क्षेत्रों से कनेक्टिविटी में भी सुधार किया। अवसंरचना के विकास से क्षेत्र में अधिक विकास एवं सुविधाएं उपलब्ध हुई है।

2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे

नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ताज एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे फरीदाबाद-नोएडा-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। यह ओखला पक्षी अभयारण्य के दक्षिणपूर्व खंड से नोएडा सेक्टर 168 तक है।

3. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन नवंबर 2016 में हुआ था। एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद से, आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा का समय कम हो गया है। पहले, यात्रा का समय लगभग छह घंटे था, और अब यह साढ़े तीन घंटे है। यह एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। पूरे एक्सप्रेसवे के साथ-साथ सर्विस रोड भी बनी है। एक्सप्रेसवे में 24 घंटे पेट्रोलिंग की सुविधा है। मरीज की सुरक्षा के लिए इसमें 10 एंबुलेंस हैं। एक्सप्रेसवे आगरा के एक गाँव एत्मादपुर मदरा से शुरू होता है और मोहन रोड के पास लखनऊ के गाँव सरोसा भरोसा में समाप्त होता है। एक्सप्रेसवे 236 जिलों और 10 गांवों से होकर गुजरता है।

4. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे :

यूपी का एक लोकप्रिय एक्सप्रेसवे- दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मिश्रण है। दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग - 3 के हिस्से के रूप में बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण के सबसे व्यस्त रुट्स में से एक पर किया गया है।

5. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

प्रधानमंत्री ने 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का

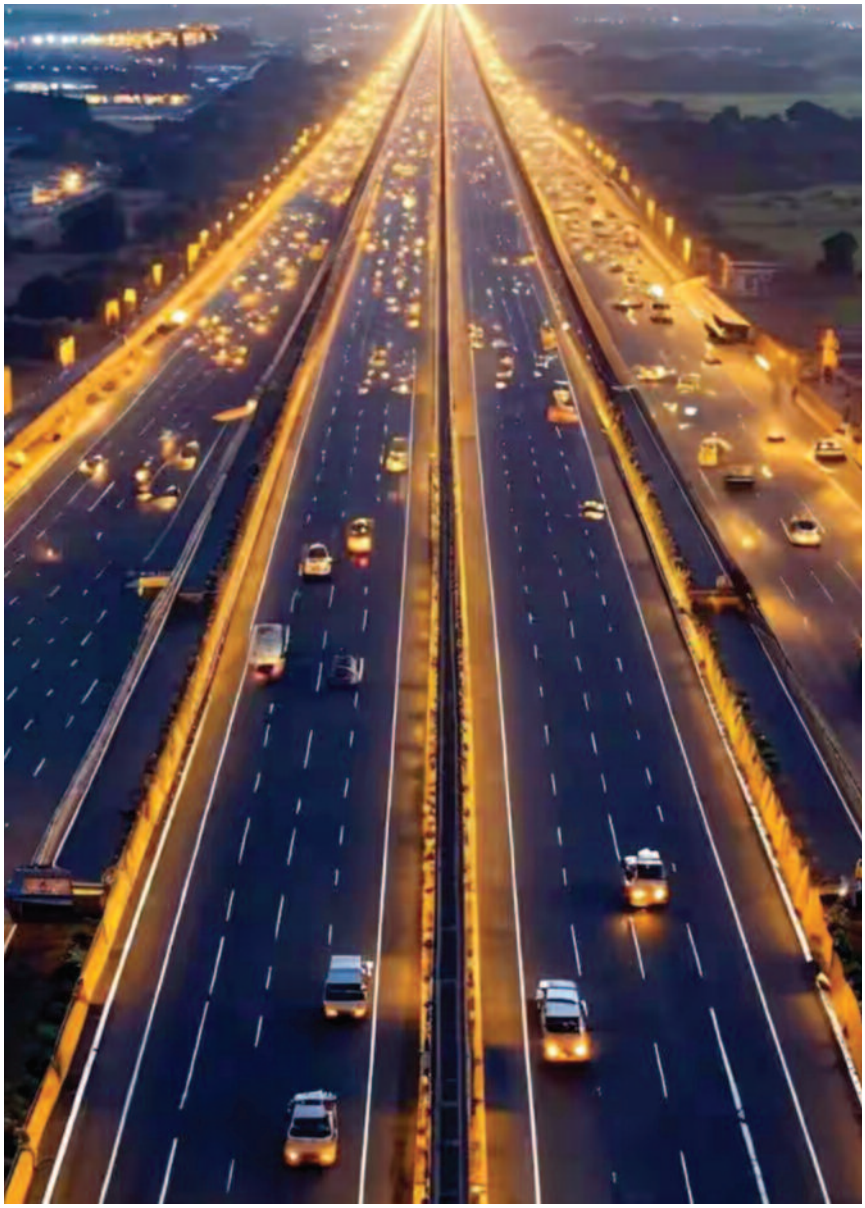

उद्घाटन किया था। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सुल्तानपुर जिले में करवाल खीरी से किया गया था। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के नौ प्रमुख जिलों को कवर करता है। इन जिलों में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ शामिल हैं। वर्तमान में लखनऊ से गाजीपुर के बीच यात्रा का समय 10 घंटे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले यात्रा का समय लगभग 15 घंटे था।

6. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण एनएच अथॉरिटी द्वारा किया गया है। यह यूपी में सबसे कम समय में बनने वाले एक्सप्रेसवे में से एक है। इसका निर्माण 28 महीने में ही हो गया था। एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पर्यटन और बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश के सात जिलों से होकर गुजरती है। इन जिलों में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल हैं। एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है।

झाँसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकोट एक्सप्रेसवे

यह एक्सप्रेसवे झाँसी और चित्रकूट धाम से शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दो राजमार्गों की घोषणा की थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 235 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और औरैया जिलों से होकर गुजरेगा।

ये दो नए एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के छह प्रमुख नोड हैं। निर्माण और संचालन शुरू होने के बाद, यूपी डिफेंस कॉरिडोर एक बड़ी सफलता होगी। झाँसी और चित्रकूट धाम एक्सप्रेसवे से पर्यटन उद्योग को लाभ होता है क्योंकि झाँसी और चित्रकूट प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

साथ ही रियल एस्टेट उद्योग पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में बदलाव लाएगा और लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। एक्सप्रेस-वे की घोषणा के बाद जमीन के रेट 15-20 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

7. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे

गोरखपुर एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है। निर्माणकार्य पूरा हो जाने के बाद, यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर और लखनऊ को जोड़ेगा। सलारपुर से, यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक मूल्य आजमगढ़ तक नजर आएंगे। यह लखनऊ और गोरखपुर के बीच यात्रा के समय को भी घटाकर 5 घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। एक्सप्रेसवे क्षेत्र में आर्थिक कॉरिडेर भी खोलेगा। यह रियल एस्टेट के विकास में भी मदद करेगा।

8. गंगा एक्सप्रेसवे : यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। यह बिजौली गांव से शुरू होकर जूदापुर दांदू गांव में समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे यूपी राज्य के लगभग 12 जिलों को कवर करेगा। एक्सप्रेसवे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना को मजबूत करने में मदद करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे की अन्य एक्सप्रेसवे से भी निर्बाध कनेक्टिविटी होगी।

9. लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे

लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अपनी तरह का अनूठा एक्सप्रेसवे है। लगभग 3.5 किमी की दूरी तक एक्सप्रेसवे एनएच 25 के समानांतर होगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से शहर के ट्रैफिक में भारी कमी आएगी। एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के रूप में जाना जाता है।

10. गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे : यूपी का आगामी एक्सप्रेसवे

गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे दो औद्योगिक शहरों को जोड़ेगा। इससे यात्रा का समय घटकर तीन घंटे हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम

माता की प्रेरणा और संघ की संगत से बन गये जुझारू राजनीतिज्ञ

***नितिन** गडकरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं तथा भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। इससे पहले 2011-2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बावन वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले वे इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे कामर्स में स्नातकोत्तर हैं इसके अलावा उन्होंने कानून तथा बिजनेस मनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। वो भारत के एक उद्योगपति हैं। गडकरी सफल उद्यमी हैं। वह एक बायो-डीजल पंप, एक चीनी मिल, एक लाख 20 हजार लीटर क्षमता वाले इथानॉल ब्लेन्डिंग संयत्र, 26 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र, सोयाबीन संयंत्र और को जनरेशन ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हैं। गडकरी ने 1976 में नागपुर विश्वविद्यालय में भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की। बाद में वह 23 साल की उम्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सब को साथ लेकर चलने की खूबी की वजह से वे सदा अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे। 1995 में वे महाराष्ट्र में शिव सेना- भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए और चार साल तक मंत्री पद पर रहे। मंत्री के रूप में वे अपने अच्छे कामों के कारण प्रशंसा में रहे। 1989 में वे पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए, पिछले 20 वर्षों से विधान परिषद के सदस्य हैं और आखिरी बार 2008 में विधान परिषद के लिए चुने गए। वे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान जमीन से जुड़े एक कार्यकर्ता के तौर पर बनाई है और वे एक राजनेता के साथ-साथ एक कृषक और एक उद्योगपति भी हैं।*

से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग छह घंटे है। एक्सप्रेसवे नौ प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फरुर्खाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर शामिल होंगे।

11. गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे

गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत के तीन प्रमुख राज्यों, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा का समय कम होकर 6 घंटे हो जाएगा। गोरखपुर से सिलीगुड़ी पहुंचने में करीब 15 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल में 18.97 किमी, बिहार में 416 किमी और उत्तर प्रदेश में 84.3 किमी का होगा।

12. दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे : यूपी में आगामी एक्सप्रेसवे

सहारनपुर से गुजरने वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिसंबर 2023 तक चालू हो जाएगा। फिर भी, यह सीमा मार्च 2024 तक हो सकती है। एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय पांच घंटे से घटकर ढाई घंटे हो जाएगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा।

13. गाजीपुर - बलिया - मांझी घाट एक्सप्रेसवे : यूपी का आगामी एक्सप्रेसवे

यूपी में सबसे महत्वपूर्ण आगामी एक्सप्रेसवे गाजीपुर बलिया मांझी एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे यूपी के गाजीपुर क्षेत्र को बिहार के बक्सर से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कई चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 618 करोड़ रुपये तय किए गए। एक्सप्रेसवे दो साल में बनकर तैयार होगा।

14. गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में रोड इफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। यूपी सरकार ने गोरखपुर से शामली के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गोरखपुर-शामली एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास हो सकता है।

15. आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश में आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे छह लेन का हाई-स्पीड कॉरिडोर बनेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आगरा और ग्वालियर को जोड़ेगा। दोनों शहरों के बीच की मौजूदा दूरी करीब 121 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे आगरा के देवरी गांव से शुरू होकर ग्वालियर के सुसेरा गांव में खत्म होगा।

एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी घटकर 88 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही यात्रा का समय भी 50% कम हो जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4613 करोड़ रुपये है। एक्सप्रेसवे के 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए करीब 502.11 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना होगा। इसमें से करीब 3.18 हेक्टेयर वन भूमि होगी। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए करीब 1.5 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। आगरा में सदर और खेरागढ़ तहसील के 15 गांवों से 153 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। मध्य प्रदेश के 18 गांवों से 151 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी।

16. चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे

चित्रकूट एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव एनएच अथॉरिटी ने रखा है। यह एक्सप्रेसवे 14 किलोमीटर लंबा होगा। इस एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एनएच - 135 से जोड़ा और सरेखित किया जाएगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले हिस्से में।

यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत करीब 235 करोड़ रुपये होगी। एक्सप्रेसवे के लखनऊ एक्सप्रेसवे को फरुर्खाबाद के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की भी संभावना है। यह चार लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। हालांकि, इसे 6 लेन तक बढ़ाने का प्रावधान भी होगा।

फिलहाल एक्सप्रेसवे की प्राइमरी रिपोर्ट पर काम चल रहा है। अभी तक यह रिपोर्ट बनाने का काम मिस्व पार्क कंपनी के पास है। प्रोजेक्ट की प्री-फीजिबिलिटी पूरी हो चुकी है। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के रामघाट में खत्म होगा। पहले इसे मध्य प्रदेश की नजदीकी सीमा पर बनाया जाना था।

आठवां वेतन आयोग होगा लागू

अनिल वशिष्ठ

वैसे तो एक दम पक्के तौर पर ये फिलहाल नहीं बताया जा सकता कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद आपका वेतन कितना बढ़ेगा लेकिन पिछले वेतव आयोग की सिफारिशों के आधार पर मोटा-माटी अंदाजा तो लगा ही सकते हैं।

2025 का साल शुरू हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। बजट भी आने वाला है। मतलब साल की शुरूआत में ही राजनीतिक से लेकर आर्थिक गतिविधियां अपने उफान पर रहने वाली हैं। लेकिन तमाम कवायदों के बीच देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए 16 जनवरी की तारीख इस साल का सबसे पसंदीदा दिन हो गया है। हो भी क्यों ने मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी जो दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही कमीशन के चेयरमैन और दो मेंबर्स की नियुक्ति भी कर दी जाएगी। जिससे सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाए। वैसे तो अश्विनी वैष्णव ने इससे ज्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन खुश होने के लिए इतनी खबर भी काफी है। वैसे तो एक दम पक्के तौर पर ये फिलहाल नहीं बताया जा सकता कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद आपका वेतन कितना बढ़ेगा लेकिन पिछले वेतव आयोग की सिफारिशों के आधार पर मोटा-माटी अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। तो आज का एमआरआई स्कैन वेतन आयोग के नाम करते हैं। जानेंगे कि देश में वेतन आयोग का गठन कब से किया गया। किस आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी का सुझाव सुझाया जाता है। आठवां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है, और सबसे मेन बात इसके लागू होने से सैलरी और पेंशन में कितना पइसा बढ़ कर आएगा।

छठे वेतन आयोग में क्या हुआ?

छठे वेतन आयोग को जनवरी 2006 में लागू किया गया था। इसमें मामूली बदलाव पेश किए थे,

लेकिन फिर भी वेतन और पेंशन में सुधार हुआ। छठे वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इसलिए, 5वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन 2,750 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया था। पेंशनभोगियों को भी मामूली लाभ हुआ, न्यूनतम मूल पेंशन 1,275 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये प्रति माह हो गई।

7वें वेतन आयोग में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी

7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ। इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कई बड़े बदलाव पेश किए। सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक फिटमेंट फैक्टर था, जिसे 2.57 पर सेट किया गया था। इसका मतलब यह था कि मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाएगा, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच सभी स्तरों पर वेतन में वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग ने भी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये की सिफारिश की है, जो छठे वेतन आयोग के तहत पिछले 7,000 रुपये से अधिक है। इसके अलावा, पेंशन में भी अच्छी वृद्धि देखी गई। पेंशनभोगियों के लिए, छठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई।

कब से लागू होंगी सिफारिशें ?

जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थीं। उस आयोग का 10 वर्षों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। वैष्णव के मुताविक, इससे पहले ही नया आयोग वनाने से सिफारिशें जल्दी मिलने और उन पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। केंद्र की मंजूरी के वाद आठवें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

किन बातों पर होगा विचार ?

आयोग वेतन-पेंशन में संशोधन का सुझाव देते समय उचित फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। इसमें महंगाई, लेवर मार्केट की स्थिति और सरकारी खजाने के हाल का ध्यान रखा जाएगा। आयोग राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों से भी विचार- विमर्श करेगा क्योकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ते में किसी भी वढ़ोतरी के वाद इन पर भी सैलरी बढ़ाने का दवाव वनता है और आमतौर पर राज्य इसी तर्ज पर बढ़ोतरी करते हैं।

आयोग पे-स्केल और दूसरी चीजों में वदलाव का भी सुझाव दे सकता है। 7वें वेतन आयोग ने ग्रेड पे सिस्टम की जगह नया पैमाना पेश किया था। जस्टिस वी एन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाले छठे वेतन आयोग ने पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था का सुझाव दिया था।

उसकी सिफारिशों के आधार पर मिनिमम सैलरी 7000 रुपये महीने और अधिकतम मंथली सैलरी 80000 रुपये महीने तय हुई थी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी वेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो चुका है।

कितना बढ़ सकता है वेतन ?

यह आयोग के सामने रखे जाने वाले प्रतिवेदनों और विचार-विमर्श के बाद होने वाले निर्णय पर निर्भर करता है। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आम बजट से पहले हुई मीटिंग में मजदूर संघों ने 8वां वेतन आयोग वनाने की मांग दोहराई थी 7वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की थी। हालांकि 2.57 की मंजूरी मिली थी। इसके चलते मिनिमम वेसिक सैलरी 7000 रुपये से 2.57 गुना बढ़ाकर 18000 रुपये महीना कर दी गई। हालांकि. अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये तय किया गया, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए है। मिनिमम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये महीने हो गई थी। अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तय की गई थी।

हेयर फॉल रोकने के लिए घर पर बनाएं मेथी और प्याज का तेल, घने और लंबे होंगे बाल

आपको कम से कम एक बार घर पर इस नेचुरल तेल को बनाकर बालों में अप्लाई करना चाहिए। बता दें कि घर पर केमिकल फ्री हेयर ऑयल को बनाना बहुत आसान है। मेथी और प्याज दोनों ही हमारे बालों के लिए फायदेमंद होता है।

मुकुल शर्मा

अक्सर लोग हेयर फॉल की समस्या से जूझते रहते हैं। हेयर फॉल को रोकने के लिए लोग केमिकल बेस्ड महंगे-महंगे हेयर ऑइल का इस्तेमाल करते हैं। जिससे बाल और भी ज्यादा डैमेज होते हैं। ऐसे में आपको कम से कम एक बार घर पर इस नेचुरल तेल को बनाकर बालों में अप्लाई करना चाहिए। बता दें कि घर पर केमिकल फ्री हेयर ऑयल को बनाना बहुत आसान है। मेथी और प्याज दोनों ही हमारे बालों के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में आप इस तेल को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर अपने बालों को लंबा और घना बना सकती हैं। इस तेल से आपका हेयर हेल्थ भी काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस तेल के फायदे और इसे बनाने के तरीके के बारे में...

मेथी दाने और प्याज का मिक्सचर

घर पर हेयर ऑयल बनाने के लिए आपको 2 चम्मच मेथी दाने और एक मीडियम साइज की प्याज लें। इन दोनों ही चीजों का मिक्सचर बालों की सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले मेथी दाने को रातभर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दें और प्याज को बारीक-बारीक काट लें।

ऐसे बनाएं ये तेल

सबसे पहले भीगे हुए मेथी के दाने और बारीक कटे प्याज को अच्छे से पीस लें और इस स्मूद पेस्ट को वर्जिन कोकोनट ऑइल में करीब 10-15 मिनट तक पकाएं। अब इस तेल को ठंडा होने के बाद छान लें और इस तेल को बालों में अप्लाई करें। बालों में तेल को अप्लाई करने के बाद हेयर वॉश कर लें।

मिलेंगे बहुत सारे फायदे

बता दें कि बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप सप्ताह में दो बार इस तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं इस तेल का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बाल लंबे और घने हो सकते हैं।

इस तेल के इस्तेमाल से आपको बालों संबंधित समस्याओं से निजात मिल सकता है। आप मेथी दाने और प्याज से बने इस तेल का इस्तेमाल कर आप हेयर हेल्थ को काफी हद तक इंप्रूव कर सकती हैं।

इस आर्टिकल में हम आपको डॉक्टर शिल्पा अरोड़ा की बताई हुई स्किन और गट के लिए फायदेमंद ड्रिंक बताने जा रहे है। यह स्किन में निखार तो लाएगा भी और हेल्द के लिए भी फायदेमंद होगी।

ग्लोइंग स्किन और गट हेल्थ के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है यह ड्रिंक

खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से हेल्थ की समस्याओं से जूझना पड़ता है। बाहर के जंक फूड के खान से चेहरे पर पिंपल्स और झुर्रियां परेशान करती है। हेल्दी स्किन और गट के लिए न जाने हम सभी क्या-क्या नहीं करते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी जादुई ड्रिंक बताने जा रहे हैं, जो त्वचा को प्राकृतिक निखार देगा। इसे बनाने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है वो न सिर्फ त्वचा को निखारेंगी बल्कि आपके गट और हेल्थ के लिए काफी लाभदायक है। आइए आपको बताते हैं कांजी बनाने के फायदे।

कांजी कैसे बनाएं

- काली गाजर- 2-3
- नमक - 1 चम्मच
- पिसा हुआ सरसों पाउडर - 1 चम्मच
- काला नमक- 1/2 चम्मच
- हींग 1/3 चम्मच
- पानी 3 गिलास

ऐसे बनाएं कांजी

- इसके लिए आप काली गाजर लें और उसे 2-2 इंच के लंबे टुकड़ों में छीलकर काट लें।
- अब आप एक पैन लें और इसमें 3 गिलास पानी डालकर उबाल लें।
- पानी में उबाल आ जाए तो उसे एक बाउल में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें और फिर इसमें काली गाजर डाल दें।
- पानी का रंग गुलाबी हो जाए तो इसमें रॉक सॉल्ट, सरसों पाउडर, काला नमक और हींग डालकर अच्छे से मिला लें।
- अब इस पानी को एक जार में भरकर 3-4 दिन के लिए फेरमेंट होने के लिए रख दें।
- तैयार है आपकी कांजी ड्रिंक।

कांजी पीने के फायदे

कांजी पीने से क्लियर ग्लोइंग स्किन मिलती है। चमकदार त्वचा तभी बनती है, जब हम गट फ्रेंडली हेल्दी फर्मेंटेड फूड खाते हैं। इस ड्रिंक में फर्मेंटेशन की वजह से ये ड्रिंक प्रोबियोटिक से रिच होती है, इसके सेवन से एसिडिटी, हार्टबर्न, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग से बचाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी हेल्दी चीजें पिएंगे तो गट हेल्दी रहेगा। गट हेल्दी रहने की वजह से स्किन ग्लोइंग होगी।

शिमला और कश्मीर से कम खूबसूरत नहीं ये ऑफबीट हिल स्टेशन

मुकुल पंडित

कुछ हिल स्टेशन ऐसे भी हैं, जो कश्मीर, शिमला या मनाली से कम नहीं और लोग इनके बारे में अधिक जानते भी नहीं। ऐसे में अगर आप भी किसी ऐसे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, जहां पर पर्यटकों की भीड़ कम होती है।

घूमने के शौकीन लोग अक्सर छुट्टियां मिलते ही घूमने का प्लान बना लेते हैं। अक्सर घूमने का प्लान आते ही लोगों के मन में सबसे पहले हिल स्टेशनों के ऑप्शन पर ध्यान जाता है। हिल स्टेशन पर जाना अधिकतर लोगों को इसलिए भी पसंद होता है कि वह शहर की भीड़भाड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिता सकें। लेकिन कई फेमस हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंचती है। अगर आप भी शिमला-मनाली, मसूरी और धर्मशाला आदि हिल स्टेशनों पर जाना चाहते हैं, तो यहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक और भीड़ होती है।

हालांकि कुछ हिल स्टेशन ऐसे भी हैं, जो कश्मीर, शिमला या मनाली से कम नहीं और लोग इनके बारे में अधिक जानते भी नहीं। ऐसे में अगर आप भी किसी ऐसे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, जहां पर पर्यटकों की भीड़ कम होती है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको उन ऑफबीट हिल स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती है।

शांघड़ गांव

हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले की सैंज घाटी में एक बेहद खूबसूरत गांव है। इस गांव का नाम शांघड़ है। बता दें कि इस गांव के नजारे स्विट्जरलैंड की तरह हैं। इसी वजह से इस गांव

को कुल्लू का खज्जियार या भारत का दूसरा मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।

शांघड़

यहां के मैदान में हरे-भरे पेड़ और अद्भुत चीड़ के पेड़ों और रंग-बिरंगे छोटे घरों का नजारा बिलकुल विदेशी पर्यटन जैसे लगता है। शांघड़ में आप शंगचुल महादेव मंदिर, शांघड़ मीडोज, बरशानगढ़ झरना और रैला गांव में लकड़ी से बना टावर मंदिर है। इस जगह पर आप मन की शांति और सुंदर दृश्यों का नजारा देख सकते हैं।

ऐसे पहुंचे

शांघड़ जाने के लिए आप अपने शहर से अंबाला, चंडीगढ़ या जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। फिर सड़क मार्ग से मनाली जाएं। इसके बाद शांघड़ पहुंचने के लिए मनाली से सैंज का सफर स्थानीय बस से कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्लू हवाई अड्डा पहुंचकर भंतर से सैंज के लिए टैक्सी या बस पकड़ सकते हैं।

कनातल

यदि आप छिपे हुए खूबसूरत हिल स्टेशनों की तलाश में हैं, तो उत्तराखंड के कनातल हिल स्टेशन पर जा सकते हैं। कनातल में सीमित सैलानी आते हैं और प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठाने के लिए और भीड़-भाड़ से दूर सुकून के दो पल बिताने के लिए यहां पहुंच सकते हैं। यहां पर आप कैंपिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं। यह हिल स्टेशन देहरादून से 78किमी की दूरी पर है। मसूरी से कनातल 38 किमी और चंबा से 12 किमी दूर यहां पर पहुंचना बहुत आसान है।

ऐसे पहुंचें

कनातल हिल स्टेशन की सैर के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन से आगे बस का सफर कर सकते हैं। अगर आप मसूरी या चंबा में हैं, तो आप भी टैक्सी या स्थानीय बस से कनातल की सैर कर सकती हैं।

कलगा गांव

ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को कलगा गांव जाना चाहिए। यहां पर कलगा-बुनबुनी-खीरगंगा ट्रैक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बता दें कि इस 28 किमी लंबे ट्रैक को पूरा करने में 3 दिन का समय लग सकता है। यह गांव और ट्रैक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में पुलगा डैम के पास स्थित है। ट्रैकिंग के अलावा आप यहां पर पहाड़ी की चोटी से मणिकर्ण घाटी का अद्भुत नजारा दिखता है। तो वहीं सूर्यास्त के बाद यहां का नजारा काफी मनमोहक होता है।

ऐसे पहुंचे कलगा

कुल्लू जिले के भुंतर तक सड़ और हवाई मार्ग से जा सकते हैं। यहां से हवाई अड्डे से 25 किमी की दूरी पर मणिकर्ण है। जहां के लिए बहुत आसानी बस या टैक्सी मिल जाती है। मणिकर्ण से महज 10 किमी की दूर कलगा गांव है। जहां से ट्रैक शुरू होता है।

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर बैन लगाना कितना कारगर...?

अरुण मिश्रा

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कदम उठाया, जिसके बाद दुनिया उसकी ओर निहारने लगी। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने वाला बिल पास कर दिया। सवाल है कि इस तरह के कानूनी उपाय बच्चों के लिए कितने कारगर हो सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ?

ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक बिल पास किया है। इसके मुताबिक, 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक बच्चों की पहुंच रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर डाली गई है। अगर कंपनियां नाकाम रहीं, तो उन पर भारी-भरकम जुमार्ना लग सकता है। ऐसा कानून लाने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है।

मतलब, कानून अमल में आने के बाद बच्चे, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहां तक कि अपने माता-पिता की सहमति से भी नहीं। इस तरह के कानूनी उपाय कुछ संभावनाएं जगाते हैं, पर कुछ आशंकाएं भी पैदा करते हैं।

कानून से बदलेंगे हालात?

सबसे बड़ा सवाल तो यही है। ऑस्ट्रेलिया ने जैसा कानून पारित किया है, उससे तुरत-फुरत हालात बदलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पर इतना जरूर है कि यह कानून दुनिया के बाकी देशों को भी इस दिशा में सोचने को मजबूर करता है। वैसे तो समाज में ऐसे कई अपराध दिन-रात होते रहते हैं, जिनसे निपटने के लिए सख्त कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन इस बात से कानून की उपयोगिता या सार्थकता खत्म नहीं हो जाती। हां, इन्हें लागू करने के तौर-तरीकों पर भले ही सवाल खड़े हो सकते हैं।

इसी तरह, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कंपनियों पर नकेल कसा जाना, उनके लिए गाइडलाइन तय होना अच्छी बात है। आखिरकार किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की मौजूदगी का मोटा मुनाफा भी तो कंपनियों की झोली में ही जाता है। पर सब कुछ कानून या कंपनियों के भरोसे ही छोड़ देना समझदारी नहीं है। बच्चों के घर वालों को भी आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी।

टेक्नोलॉजी का लोचा

कानून सही तरीके से अमल में आ सके, इस बारे में एक बड़ी चिंता तकनीकी पक्ष को लेकर भी है। आशंका जताई जा रही है कि जो बच्चे टेक्नोलॉजी को चकमा देने के खेल में माहिर होंगे, वे श्ठठ का उपयोग कर, अपनी उम्र गलत बताकर या 16 साल से ज्यादा उम्र के सदस्य के अकाउंट त्रमें लॉगइन कर बैन को नाकाम कर सकते हैं। यह आशंका बेवजह नहीं है, इसलिए इसका तोड़ पहले ही निकालना

होगा। बैन लागू करने के लिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा दमदार सिस्टम लाना होगा।

इसमें अकाउंट बनाते समय यूजर को बायोमेट्रिक सिस्टम या किसी खास तरह की आईडी डालने और उसे वेरिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। आजकल हर मर्ज की एक दवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) को ही बताए जाने का चलन है। मुमकिन है कि यह अक यूजर की रुचियों और गतिविधियों को देखकर या दूसरे तरह के डेटा के आधार पर उसके बालिग-नाबालिग होने की पहचान कर दे। चाहे जो भी हो, नया कानून लागू होने की राह में आने वाली चुनौतियों पर सबकी नजर बनी रहेगी।

घरवालों की जिम्मेदारी

सिर्फ सोशल मीडिया ही क्यों, हर अच्छी-बुरी बातों के बारे में बच्चों को उचित जानकारी देना घरवालों की जिम्मेदारी होती है। माता-पिता की जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाती है कि अक्सर बच्चे उन्हें ही अपना रोल-मॉडल मान बैठते हैं। ऐसे में बच्चों के घरवालों को भी कुछ ठोस उपाय करना चाहिए।

सबसे पहली बात तो यह कि बच्चों के लिए स्क्रीन-टाइम की लिमिट तय की जानी चाहिए, चाहे वे किसी उपयोगी काम के लिए ही उनका इस्तेमाल कर रहे हों। कई बार बच्चे पढ़ाई-लिखाई, जरूरी असाइनमेंट या डेटा निकालने के लिए गैजेट्स का सहारा लेते हैं। लेकिन इन कामों की भी अवधि और समय सीमित किए जाने की जरूरत है। बच्चों पर नजर रखा जाना भी जरूरी है। उनके एप्लिकेशन और अकाउंट चेक किया जाना चाहिए।

अगर बच्चों के परिजन भी अपने स्क्रीन-टाइम में कमी ला सकें, तो इसका बच्चों पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा। बेहतर हो कि हर परिवार अपने लिए एक डिजिटल प्लान तैयार करे। इसमें घर के भीतर 'डिवाइस फ्री जोन' तय हों। भोजन के वक्त या सोने से कुछ घंटे पहले गैजेट्स का इस्तेमाल कोई भी न करे।

चाहिए बेहतर विकल्प

एक सवाल यह भी उठता है कि बच्चे अपना दिल बहलाने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल न करें, तो आखिर करें क्या? जाहिर है, इसका समाधान गंभीरता से ढूंढे जाने की जरूरत है।

इस बारे में ऑस्ट्रेलिया के ढट एंथनी अल्बनीज की बात सुनी जानी चाहिए, जो उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए कहा था। अल्बनीज ने कहा था कि वह चाहते हैं कि आस्ट्रेलिया के युवा फोन छोड़कर फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस जैसे खेल खेलें। साफ है कि वह बच्चों को फुर्सत के वक्त किसी आउटडोर एक्टिविटी में व्यस्त रखे जाने के पक्ष में हैं, जिससे वे सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं।

अगर अपने आस-पास नजर दौड़ाएं, थोड़ा इंटरनेट खंगालें, तो मालूम पड़ेगा कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, बल्कि देश-दुनिया में हर जगह किशोरों-युवकों को आउटडोर गेम्स या दूसरी शारीरिक गतिविधियों से जोड़ा जाना जरूरी है। कम से कम उन्हें घर के भीतर ही किसी रचनात्मक चीज या हॉबी से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ऐसा करने से उनके शारीरिक और मानसिक सेहत पर सकारात्मक असर पड़ने की पूरी संभावना बनती है।

कुल मिलाकर, जिन चीजों से बच्चों को रोका जाना है, उनकी जगह एक दमदार विकल्प तो पेश करना ही होगा। तभी ऊर्जा से लबालब भरी युवा पीढ़ी की मानसिकता सही दिशा में मोड़ी जा सकेगी।

सोशल मीडिया से दिक्कत क्या है?

आज के दौर में सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हर उम्र के लोगों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जहां तक कम उम्र के बच्चों की बात है, उन पर सोशल मीडिया से जुड़ने के कई घातक नतीजे हो सकते हैं। कई रिसर्च में इस तरह के तथ्य सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताने से छोटे बच्चों में डिप्रेशन, चिंता और दूसरों से अपनी तुलना करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। नींद पर बुरा असर पड़ता है। स्क्रीन-टाइम बढ़ने से उनके मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा आ सकती है।

सोशल मीडिया से चिपके रहने पर बच्चे रीयल लाइफ में परिवार और दोस्तों से दूर हो सकते हैं। इससे उनका सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो सकता है। आजकल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के घातक और जानलेवा स्टंट वायरल होते रहते हैं। कम उम्र के बच्चे अगर इनकी नकल करने की कोशिश करते हैं, तो नतीजों का अनुमान लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और हर छोटे बच्चे से मानसिक रूप से इतनी परिपक्वता की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे अपना भला-बुरा खुद सोच-समझ सकें। खतरे और भी हैं। वैसे तो साइबर फ्रॉडिये किसी भी उम्र के लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे, फिर भी कम उम्र के बच्चे उनके आसान शिकार हो सकते हैं। ऐसे में बैंक खातों और गोपनीय डेटा की सुरक्षा की खातिर भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में ही भलाई है।

रामबाण हैं गुड़ वाला मखाना हेल्थ को मिलेंगे गजब के फायदे

मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, पोटैशियम और फॉस्फोरस भी होती है। वैसे तो मखाना स्नैकिंग के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। इसे आप गुड़ के साथ मिलाकर एक अच्छा स्नैक बना सकते हैं। गुड़ का मखाने के स्वाद ही टेस्टी होगा और यह आपको ठंड से भी बचाएगा। आइए आपको बताते हैं इसे कैसे बना सकते हैं।

गुड़ मखाना बनाने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए

- 1/2 कप गुड़
- 2 बड़ी कटोरी मखाना
- 1 बड़ा चम्मच तिल के बीज
- 1 चम्मच पानी
- नमक की चुटकी

डॉ. निमित त्यागी

कैसे बनाएं गुड़ मखाना?

गुड़ मखाना बनाने के लिए आप एक पैन लें और उसमें घी गर्म करें। अब इसमें मखाने और नमक डालकर भून लें। जब तक की मखाने पूरी तरह से क्रंची हो जाएं। अच्छे से मखाने सिक जाएं तो इन्हें एक बर्तन में अलग निकालकर रख दीजिए। फिर कढ़ाई में घी गर्म करें और इसमें गुड़ मिला लें।

इसे अच्छे से मिक्स करते रहे हैं और पानी मिलाएं जब ये पतला हो जाए तो इसमें मखाना मिला दें। अब इसमें आप तिल के बीज डालें और अच्छे से मिक्स करें। जब मखाने गुड़ के साथ मिल जाएं तो आप इसे बटर पेपर पर निकाल लें और ठंडा होने के बाद एक-एक मखाने को अलग कर दें।

इन मखाने को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें। स्नैकिंग के लिए गुड़ मखाना आपका तैयार है।

मखाना सेहत के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। मखाना पोषक तत्वों की खदान है और साथ ही गुड़ हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। सर्दियों के दौरान आप गुड़ वाला मखाना घर पर बना सकते हैं यह एकदम कैरेमल पॉपकॉर्न की तरह लगता है।

संजय बैंसला

सर्दियों में शकरकंद खाने से मिलते हैं ढेरों फायदे

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कुछ चीजों की डिमांड तेजी से बढ़ती है। इन्हीं में से एक शकरकंद है। कुछ लोग इसको भूनकर खाते हैं, तो कुछ लोग उबालकर खाते हैं। इसकी गिनती फल और सब्जियों दोनों में की जाती है और यह ठंड में खूब बिकता है। शकरकंद न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। शकरकंद में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं। बता दें कि शकरकंद में काबोर्हाइड्रेट और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसकी वजह से लोग आलू की जगह शकरकंद खाने की सलाह देते हैं। शकरकंद में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है। वहीं इसमें मौजूद फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसके अलावा शकरकंद में जिंक, काबोर्हाइड्रेट और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है या ठंडी। तो इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि शकरकंद की तासीर ठंडी होती है या गर्म।

ठंडा या गर्म होता है शकरकंद

बहुत से लोगों को शकरकंद खाना पसंद होता है। लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है या गर्म। तो बता दें कि शकरकंद की तासीर गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसका अधिक सेवन किया जाता है। क्योंकि इसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और फ्लू जैसी समस्याओं से बचाता है। साथ ही यह शरीर को सर्दी भी प्रदान करता है।

शकरकंद में काबोर्हाइड्रेट और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसकी वजह से लोग आलू की जगह शकरकंद खाने की सलाह देते हैं। शकरकंद में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है।

इन समस्याओं में है फायदेमंद

सर्दियों में शकरकंद का सेवन स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है। इसको खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। शकरकंद में विटामिन सी की अच्छा मात्रा पाई जाती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। शकरकंद में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसको खाने से पाचन में सुधार होता है।

अगर आप खाना पचा नहीं पा रहे हैं, तो आपको इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। सर्दियों के मौसम में लोग एक्सरसाइज करने में आलस करते हैं। जिसकी वजह से वजन तेजी से बढ़ता है। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में शकरकंद को शामिल करते हैं, तो फाइबर से भरपूर होने की वजह से आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और आप ज्यादा खाने से बच जाएंगे।

कब न खाएं शकरकंद

हम में से बहुत से लोग कभी भी शकरकंद का सेवन कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रात के समय शकरकंद खाने से बचना चाहिए और यदि आप मधुमेह या फिर मोटापे से पीड़ित हैं, तो आपको दोपहर 12 से 3 बजे के बीच शकरकंद खाना चाहिए। हालांकि आप शकरकंद को कई तरह से खा सकते हैं। आप इसको उबालकर, भाप में पकाकर या फिर बेक करके खा सकते हैं। आप सर्दियों में इसका सूप बनाकर भी सेवन कर सकते हैं।

रितिक रोशन के डांस की दीवानी है दीवानी

दुनिया के दस हैंडसम पुरुषों में टॉप पोजीशन पाने वाले सिनेस्टार रितिक रोशन के डांस की पूरी दुनिया दीवानी है। उनकी प्रतिभा को देखकर कोई भी कह सकता है कि कोई नेपोटिज्म के बूते ही स्टार नहीं बन जाता। इसके लिये खासी मेहनत भी करनी पड़ती है।

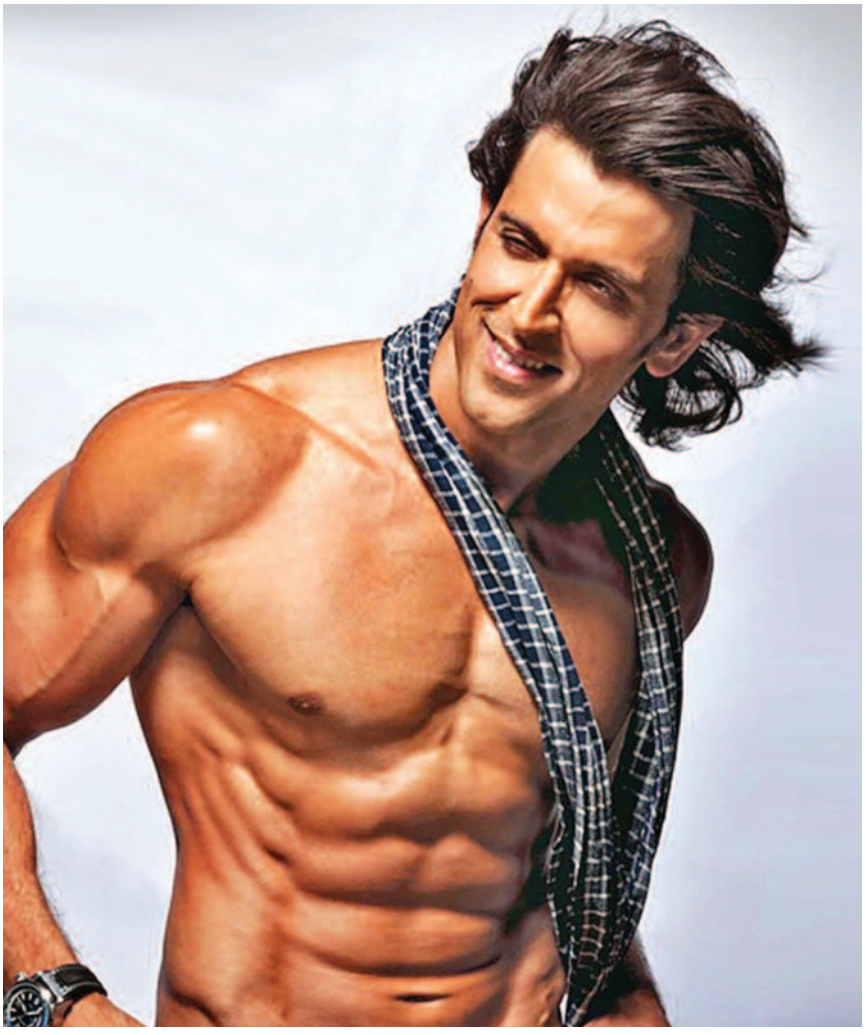

आकांशा गर्ग

नीली आंखों, घुंघराले बाल, गुलाबी और गठीले लम्बे बदन वाले रितिक रोशन बॉलिवुड के ग्रीक गॉड कहे जाते हैं। अपनी आकर्षक पर्सनैलिटी की वजह से वे अक्सर चर्चा में रहते हैं। रितिक की काया और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि लोग इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाते। यही वजह है कि वे दुनिया के मोस्ट हैंडसम मैन की लिस्ट में कई बार आ चुके हैं।

टॉप पोजिशन पर पहुंचने वाले हैंडसम लोगों की प्रतियोगिता में क्रिस इवान, डेविड बैकहम, रॉबर्ट पैटिनसन जैसे सितारों को कड़ी टक्कर देते हुए रितिक पहले नंबर पर जगह बनाने में यूं ही कामयाब नहीं हुए हुए। इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और शानदार अभिनय का मेल रहा है। कम ही लोगों को पता होगा कि रितिक रोशन दुनिया के सबसे हैंडसम एक्टर्स की लिस्ट में साल 2018 से लगातार टॉप पोजीशन पर हैं।

रितिक बॉलिवुड के आकर्षक शख्सियतों में से एक हैं, जिन्होंने अपने लुक से ही नहीं, बल्कि अपने डांस से भी दर्शकों को दीवाना बनाया है। बॉलिवुड के सबसे टैलंटेड ऐक्टर्स में से एक रितिक अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतना जानते हैं। गुड लुक्स, चार्म और दिल चुरा लेने वाली

उनकी स्माइल किसी को भी आसानी से दीवाना बना देती है।

रितिक ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी और फिल्म 'कहो न प्यार है' से उन्हें बॉलिवुड में ब्रेक मिला। अपनी इस डेब्यू फिल्म से ही रितिक लाखों दिलों की धड़कन बन गए। इसके बाद तो उन्होंने 'मिशन कश्मीर', 'कभी खुशी कभी गम', 'मैं प्रेम की दीवानी हूं', 'कोई मिल गया', 'कृष', 'धूम 2' और 'सुपर 30' जैसी कई शानदारों फिल्मों की लाइन लगा दी। रितिक साल (2011-2012) में दुनिया के 50 सबसे सेक्सी एशियन पुरुषों की लिस्ट में भी टॉप पर रह चुके हैं। रितिक की फिल्म 'सुपर 30' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 140 करोड़ की शानदार कमाई की है।

यह बात रितिक के फैन्स को भी नहीं पता होगी कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म से पहले हैंडसम अभिनेता जितेंद्र के संग उनकी एक फिल्म में डांस किया था। 50 साल के हो चुके इस एक्टर का जन्म 10 जनवरी, 1974 को मुंबई में हुआ था। पिता राकेश रोशन अपने जमाने के सुपर हीरो रहे, जबकि चाचा दादा और चाचा संगीतकार। लेकिन रितिक ने इन सबसे अलग पहचान अपनी काबिलियत और मेहनत से बनाई है। न केवल बॉलीवुड में, बल्कि हॉलीवुड में भी हीरो बनकर।

ऋतिक रोशन को फिल्म इंडस्ट्री में आए करीब तीन दशक हो चुके हैं। अपनी डीसेंट और कूल पर्सनेलिटी की वजह से उन्होंने फैंस के बीच एक खास स्थान हासिल किया है। उनके बेजोड़ अभिनय और उनके डांस की दीवानी तो सारी दुनिया है।

फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले ऋतिक रोशन कि दादा म्यूजिक डायरेक्टर और दादी क्लासिकल सिंगर थीं। उनके चाचा राकेश रोशन भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पिता राकेश रोशन बॉलीवुड फिल्मों में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर हैं। वे भी अपने जमाने के लोकप्रिय हीरो रहे हैं। उनके नाना जे. ओम प्रकाश भी जाने-माने प्रोड्यूसर रहे हैं। कुल मिलाकर रितिक रोशन बॉलवुड के ऐसे अकेले सिनेस्टार हैं, जिनके व्यक्तित्व को दुनिया के दूसरे देशों में भी पसंद किया जाता है।

पहली फिल्म में मिली सौ रु. फीस

वैसे तो ऋतिक रोशन ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में फिल्म 'कहो ना प्यार है' से की थी, मगर इससे पहले भी वे कुछ फिल्मों का हिस्सा रह चुके थे। कभी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर तो कभी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। ऋतिक की सबसे पहली फिल्म अपीयरेंस साल 1980 में आई फिल्म 'आशा' से थी। इस मूवी में वे जितेंद्र संग एक गाने पर डांस करते नजर आए थे। गाने के बोल थे 'जाने हम सड़क के लोगों से'। इस गाने में नन्हें ऋतिक रोशन महज 7-8 साल के थे। यह फिल्म नाना जे ओमप्रकाश ने प्रोड्यूस की थी। नन्हीं उम्र में भी ऋतिक का डांस इतना परफेक्ट था कि सभी इंप्रेस हो गए थे। यही नहीं, इसके लिए उन्हें सौ रुपए फीस भी मिली थी, जो उस जमाने में ऋतिक के लिए एक भारी-भरकम पॉकेट मनी से कम नहीं होगी।

आईपीएल: कौन-कितना मजबूत

सऊदी अरब के जेद्दा में आईपीएल 2025 के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी ने अपनी टीमें बना ली हैं और अब इस सवाल को लेकर बहस छिड़ी है कि कौन सी टीम कितनी मजबूत है और अगले साल की शुरुआत में होने वाले आईपीएल टूनार्मेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में कौन सी टीमें पहुंचेंगीं? इस बार नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप सिंह और युजवेन्द्र चहल को लेकर तो चर्चा है ही, इस सवाल को लेकर आश्चर्य भी जताया जा रहा है कि कई उन खिलाड़ियों को नीलामी में कोई भाव ही नहीं दिया गया, जो क्रिकेट के धुरंधर हैं।

182 खिलाड़ियों पर लगी बोली

दो दिन चली मेगा नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें से 182 खिलाड़ी बिके, जबकि 395 खिलाड़ियों के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई। 182 में से 62 विदेशी खिलाड़ी रहे। 10 टीमों ने मिलाकर कुल आठ राइट टू मैच कार्ड इस्तेमाल किए। नीलामी में खिलाड़ियों को खरीदने के लिये 639.15 करोड़ रुपये खर्च किए। क्रिकेट के जानकारों का कहना है कि आईपीएल के लिये दर्शकों की दीवानगी

हरेन्द्र शर्मा

जिस तरह बढ़ रही है, खिलाड़ियों को महंगी से महंगी कीमत पर खरीदना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। फिलहाल तो यह देखना है कि नीलामी के बाद कौन सी टीम ताकतवर होगी? सुनील गावस्कर, कपिल देव, मदनलाल जैसे दिग्गज पूर्व खिलाड़ियों का कहना है कि सभी टीमें संतुलित हैं और हर टीम में मैच का रुख पलट देने की कूवत है। लिहाजा यह कहना बेहद मुश्किल होगा कि कौन सी टीम किस टीम से कमतर होगी। पांच बार की विजेता मुंबई इंडियंस में इस बार भी मजबूत भारतीय खिलाड़ी खेलते दिखेंगे। हालांकि विदेशी खिलाड़ियों में ज्यादातर अनुभवहीन हैं, लिहाजा उनका कड़ा इम्तिहान होगा। इस टीम में विदेशी खिलाड़ियों के रूप में ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सैंटनर के अलावा बाकी सभी नए हैं। ऑलराउंडर विल जैक्स, तेज गेंदबाज रीस टॉपले व लिजाड विलियम्स और स्पिनर अल्लाह गजानफर ने अब से पहले कभी आईपीएल टूनार्मेंट नहीं खेला है। बेवन-जॉन जैकब्स और रेयान रिकेल्टन भी पहली बार आईपीएल खेलेंगे।

चेन्नई ने आर अश्विन को 10 सीजन बाद वापस लिया है। इस बार वे रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर स्पिन की कमान संभालेंगे। चेन्नई ने अफगानिस्तान के नूर अहमद को जोड़कर अपने स्पिन आक्रमण को बहुत मजबूत किया है। इस टीम से महेन्द्र सिंह धोनी एक बार फिर आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी, दीपक हुड्डा और श्रेयस गोपाल इस टीम की ताकत बनेंगे।

बैंगलोर के रॉयल चेलेंजर्स ने ओपनिंग के लिए विराट कोहली के साथी के तौर पर विस्फोटक फिल सॉल्ट को खरीदा है। इस टीम में हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार अनुभवी तेज गेंदबाज होंगे। बल्लेबाज रजत पाटीदार, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा सरीखे बल्लेबाज कोहली की ताकत साबित होंगे। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में एक ओर पैट कमिंग्स, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल जैसे तेज गेंदबाजों की तिकड़ी और दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, ट्रेविस हेड और

अनिकेत वर्मा धुरंधर बल्लेबाज प्रतिद्वंदी टीम को चुनौती पेश करते नजर आएंगे। कोलकाता ने आईपीएल 2024 में खिताब जीतने वाली टीम के छह खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि छह अन्य खिलाड़ियों को नीलामी से खरीदा। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च करके यह संकेत दिया है कि वेंकटेश ही इस टीम के कप्तान होंगे। इस बार टीम में सॉल्ट और स्टार्क की जगह क्विंटन डी कॉक और एनरिक नॉर्त्ज/स्पेंसर जॉनसन को टीम में शामिल किया गया है। पंजाब ने श्रेयस अय्यर को खरीदने के लिए 26 करोड़ 75 लाख रुपये खर्च किए। इस धुरंधर बल्लेबाज के साथ इस टीम में शशांक सिंह, ग्लैन मेक्सवेल, मार्क्स स्टॉइनिस, हरप्रीत बरार, मार्क यानसेन, अजमतुल्ला उमरजई जैसे घातक बल्लेबाज होंगे। दूसरी ओर अर्शदीप सिंह, लोकी फर्ग्यूसन, यजुवेंद्र चहल जैसे अनुभवी गेंदबाज विरोधी टीम के लिये चुनौती पेश करेंगे। लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदकर उनके लिये कप्तानी के दरवाजे खोल दिये। इस चमत्कारी विकेटकीपर बल्लेबाज का बल्लेबाजी में साथ एडेन मारक्रम, डेविड मिलर, आयुष बदोनी, मैथ्यू ब्रीट्जके, निकोलस पूरन, आर्यन जुयाल, मिचेल मार्श देंगे तो गेंदबाजी का कमाल रवि विश्नोई, एम सिद्धार्थ, आवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान और आकाशदीप दिखाएंगे। इस सीजन में दिल्ली की कप्तानी कौन करेगा, अभी तो इसे लेकर असमंजस है। अक्षर पटेल कप्तान बनेंगे या फिर केएल राहुल? अक्षर टीम में राहुल से ज्यादा महंगे हैं। पिछले आईपीएल में राहुल की कप्तानी कुछ खास नहीं रही थी। इस टीम के मालिक ने केएल राहुल के अलावा बल्लेबाज के तौर पर विदेशियों को ही प्राथमिकता दी है। हालांकि गेंदबाजी में एक से एक शानदार खिलाड़ियों को खरीदा है। मैकगर्क, स्टब्स, हैरी ब्रुक, डुप्लेसिस इस टीम की बल्लेबाजी संभालेंगे तो कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार, टी. नटराजन, मोहित शर्मा और दुष्मंथा चमीरा गेंदबाजी का कमाल करते दिखेंगे। राजस्थान रायल्स ने नीलामी में गेंदबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर, वानिंदु हसरंगा और महेश तीक्षणा, नीतीश राणा जैसे धुरंधर गेंदबाजों को खरीदकर विरोधी टीमों को चुनौती पेश करने के संकेत दे दिये। इस टीम में गजब की फार्म पर चल रहे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शिमरान हैटमायर, शुभम दुबे और ध्रुव जुरेल, रियान पराग किसी भी प्रतिद्धंदी टीम का गणित बिगाड़ने की हैसियत में होंगे। वहीं, गुजरात ने 12 मार्की खिलाड़ियों में से तीन जोस बटलर, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा को लेकर शानदार काम किया है। प्रसिद्ध कृष्णा को खरीदकर टीम ने अपनी बॉलिंग लाइनअप मजबूत की। मध्य क्रम में गुजरात को वॉशिंगटन सुंदर से उम्मीदें होंगी। शुभमन गिल, साईं सुदर्शन, राहुल तेवतिया टीम की बल्लेबाजी में जोश भरते नजर आएंगे।

नन्हा वैभव रहेगा आकर्षण का केन्द्र

महज 13 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2025 टूनार्मेंट में सबसे ज्यादा आकर्षण का केन्द्र बनेंगे। मेगा नीलामी में इस किशोर उम्र खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स ने एक करोड़ दस लाख रुपए में खरीदा है। छोटी उम्र में तमाम रिकार्ड अपने नाम कर चुका यह बल्लेबाज दुनिया भर के क्रिकेटरों को अपनी प्रतिभा से चौंका चुका है। वैभव में आईपीएल में सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

इन्हें नहीं मिला कोई खरीदार

जिन दिग्गज क्रिकेटरों को इस बार आईपीएल की नीलामी में खरीदार नहीं मिला, उनमें पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर, भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, जेम्स एंडरसन, पृथ्वी शॉ और केन विलियम्सन शामिल हैं। नीलामी की शुरूआत में देवदत्त पडिक्कल और अजिंक्य रहाणे जैसे भारतीय खिलाड़ियों को भी किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन बाद में आरसीबी ने पडिक्कल और केकेआर ने रहाणे को अपनी टीम में शामिल कर लिया। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस ने उनकी बेस प्राइस 30 लाख रुपये में खरीदा है।

CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
VCB PANEL, CRP,
TRANSFORMER, RMU ETC

SECURE METERS LTD.
ENERGY METER
(POSTPAID/PREPAID/
SOLAR/ABT)

SECURE

MITSUBISHI ELECTRIC
MCB/MCCB/ACB/
CONTRACTOR/DB

MITSUBISHI ELECTRIC

Kumar Enterprises

GF-150 | DURGA TOWER | RDC | RAJ NAGAR | GHAZIABAD (UP) - 201001
TEL. : 0120-4137613 | EMAIL : ke.ghaziabad@gmail.com
SANJEEV KUMAR 9268566079

NABCB
QMS 008
AN ISO 9001 -2000 COMPANY

IS:8931

CM/L-3228449

supreme
luxury bathing

Assuring Excellence in Bath Faucets

SHANTI NATH MANUFACTURERS
A-2/14, Sector-17, Kavi Nagar, Industrial Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)
Website: www.shantinathsupreme.com; E-mail: snmsupreme@gmail.com
Toll Free No.: 18001035266; Mob.: 8860638266

देश में
नंबर वन
उत्तर प्रदेश

खुशहाल किसान
यूपी की पहचान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत
2.80 करोड़ से अधिक किसानों को
₹79,362 करोड़ हस्तांतरित

किसान कल्याण मिशन

- 46 लाख किसानों को ₹2.56 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान
- 14.78 लाख से अधिक निजी नलकूप धारक किसानों का 100 प्रतिशत सिंचाई का बिजली बिल माफ
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 72,719 सोलर पंप किसानों को वितरित
- 36 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, 25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश